CNews सिटी चीफ

सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-310
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

अपने आपमें विश्वास रखने का आदर्श ही हमारा सब से पड़ा सहायक

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

इंदौर, शुक्रवार 14 फरवरी 2025

मोहन भागवत की सभा को बंगाल में इजाजत नहीं, हाईकोर्ट पहुंचा आरएसएस

कोलकाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पश्चिम बंगाल इकाई ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया और 16 फरवरी को पूर्वी बर्दवान जिले के बर्दवान शहर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सभा के लिए पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने को चुनौती दी। जिला पुलिस ने इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया कि चूंकि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए उस दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। जिला पुलिस ने अनुमति देने से इनकार करते हुए यह भी कहा कि आरएसएस प्रमुख की प्रस्तावित सभा स्थल के पास एक स्कूल है। हालांकि, एक प्रतिवाद यह भी है कि चूंकि बैठक रविवार को होगी, इसलिए परीक्षा प्रक्रिया बाधित होने का सवाल ही नहीं उठता।

गुरुवार को आरएसएस की राज्य इकाई ने पुलिस की अनुमति न दिए जाने को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की उम्मीद है। भागवत फिलहाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने आरएसएस के विभिन्न राज्य पदाधिकारियों से मुलाकात की और राज्य में संगठन के नेटवर्क का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की।

इसलिए खास है भागवत का बंगाल दौरा आरएसएस की रविवार को बर्दवान में प्रस्तावित बैठक मध्य बंगाल के जिलों पर ध्यान केंद्रित करने की कवायद का हिस्सा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह दौरा दो मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है, जिनमें से पहला 2025 में होने वाला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है।

दूसरा, यह दौरा पड़ोसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के निरंतर उत्पीड़न की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिसका स्पष्ट प्रभाव पश्चिम बंगाल में महसूस किया जा रहा है, जिसकी बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है।

पीड़ित महिला डॉक्टर के माता-पिता से मिले थे संघ प्रमुख 8 फरवरी को भागवत ने आर.जी. कर बलात्कार और हत्या मामले में पीड़ित महिला डॉक्टर के माता-पिता के साथ लंबी बैठक की थी। माता-पिता ने अपनी बेटी के लिए न्याय सुनिश्चित करने में आरएसएस प्रमुख के हस्तक्षेप की मांग की है। बैठक के दौरान, पीड़िता के माता-पिता ने, विशेष रूप से, भागवत से अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि केंद्र आवश्यक कदम उठाए और उचित निर्देश दे ताकि भविष्य में मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और इस जघन्य अपराध के पीछे के सभी मास्टरमाइंड को दंडित किया जा सके। भागवत ने उन्हें इस मामले पर अपना आश्वासन दिया।

संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल संबंधी जेपीसी की रिपोर्ट पेश, भारी हंगामा

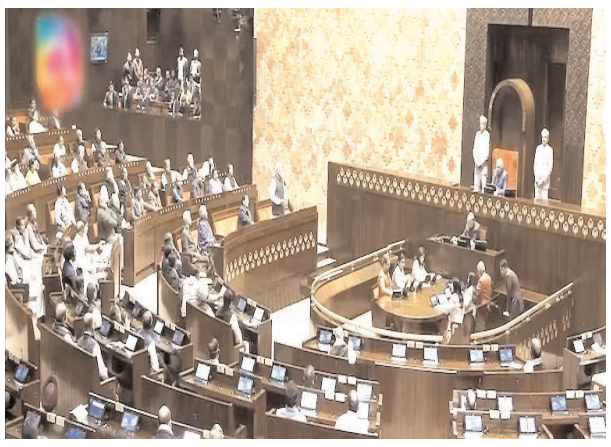

नई दिल्ली। संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का गुरुवार को आखिरी कामकाजी दिन था। इस दौरान वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई। लोकसभा में इसे दोपहर दो बजे के बाद पेश किया गया, जबकि राज्यसभा में दिन की कार्यवाही शुरू होते वक्त ही इसे पटल पर रखा गया। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखा। इससे पहले राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्षी दलों के भारी हंगामा शुरू कर दिया। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे सांसद आसन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे राष्ट्रपति का एक संदेश सदन में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन में व्यवस्था बनाने की अपील की। हालांकि, इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। धनखड़ ने कहा कि भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति पद पर आसीन पहली आदिवासी महिला का संदेश है यह और इसे सदन में पेश न होने देना उनका अपमान होगा। धनखड़ ने हंगामा कर रहे सांसदों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट से कई सदस्य असहमत हैं। उन नोटों को हटाना और हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। असहमति रिपोर्ट को हटाने के बाद पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की मैं निंदा करता हूं। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार ही नहीं हैं, तो उसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से पेश किया जाना चाहिए।

सीएम मोहन यादव ने कलाकारों को दिए राज्य शिखर सम्मान अलंकरण

भोपाल। मध्यप्रदेश के लिए खुशखबरी है। भोपाल के भारत भवन का रंगमंडल फिर से शुरू होने जा रहा है। इतना ही नहीं, इस रंगमंडल को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भी सहयोग मिलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत भवन में की। वे गुरुवार को को भारत भवन की 43वीं वर्षगांठ और राज्य शिखर सम्मान अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्य शिखर सम्मान के अंतर्गत सम्मानित व्यक्तियों को सम्मान पट्टिका और दो लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। यह समारोह प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मान्यता देने के लिए आयोजित किया जाता है। 2022 का राज्य शिखर सम्मान हिंदी साहित्य के लिए डॉ. उर्मिला शिरीष (भोपाल) को, 2023 का राज्य शिखर सम्मान उर्दू साहित्य के लिए महमूद अहमद सहर (उज्जैन) को, 2022 का राज्य शिखर सम्मान संस्कृत साहित्य के लिए डॉ. मिथिला प्रसाद त्रिपाठी (इंदौर) और 2023 का सम्मान डॉ. गोविंद दत्तात्रेय गंधे (उज्जैन) को प्रदान किया गया। वहीं 2022 का राज्य शिखर सम्मान शास्त्रीय संगीत के लिए विदुषी कल्पना झोकरकर (इंदौर) और 2023 का सम्मान विदुषी शाश्वती मंडल (दिल्ली) को प्रदान किया गया। शास्त्रीय नृत्य के लिए 2022 का सम्मान मोहिनी मोघे (जबलपुर) और 2023 का सम्मान विदुषी भारती होमबल (भोपाल) को प्रदान किया गया। रूपंकर कला के लिए 2022 का सम्मान ईश्वरी रावल (इंदौर) और 2023 का सम्मान हरि भटनागर (बड़ौदा) को प्रदान किया गया। नाटक के क्षेत्र में 2022 का सम्मान राम जोग (इंदौर) और 2023 का सम्मान सतीश दवे (उज्जैन) को प्रदान किया गया। दुर्लभ वाद्य वादन के लिए 2023 का सम्मान पं. सुनील पावगी (ग्वालियर) और जनजातीय एवं लोक कला के लिए 2022 का सम्मान रामसिंह उर्वेती (पाटनगढ़) और 2023 का सम्मान कैलाश सिसोदिया (धार) को प्रदान किया गया।

इंदौर के रजत पाटीदार बने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान

इंदौर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन (आईपीएल 2025) से पहले अपने कप्तान के नाम का ऐलान किया। इंदौर के रजत पाटीदार को आरसीबी का नया कप्तान बनाया गया है। फ्रेंचाइजी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट और लाइव सेशन के जरिये इस बात का ऐलान किया।

रजत पाटीदार आरसीबी के 8वें कप्तान बने हैं। आरसीबी ने मेगा ऑक्शन से पहले अपने पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस को रिटेन नहीं किया था। रजत पाटीदार इंदौर के रहने वाले हैं। 1 जून 1993 को इंदौर में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही रजत का क्रिकेट से लगाव था। उन्होंने क्रिकेट में अपनी शुरुआत एक ऑफ स्पिनर के रूप में की। धीरे-धीरे वेएक तूफानी बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 2015-16 सीजन में मध्यप्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। 2017-18 के रणजी सीजन में उन्होंने 713 रन बनाए। रजत पाटीदार की 2021 में आईपीएल में एंट्री हुई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें 20 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा। आईपीएल 2022 में वे चर्चा में आए। उन्होंने लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ प्लेऑफ में शानदार शतक लगाया। इस पारी के बाद वे आरसीबी के अहम प्लेयर बन गए। उन्होंने लीग में बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा। यही कारण था कि रजत पाटीदार को 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू करने का मौका मिला।

फ्रेंचाइजी ने कोहली का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें विराट ने पाटीदार को कप्तान बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं और टीम के अन्य सदस्य आपके साथ हैं, रजत। जिस तरह से आपने इस फ्रेंचाइजी में प्रगति की है और जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया है, आपने सभी प्रशंसकों के दिलों में जगह बनाई है। आप इसके हकदार हैं। इस बीच रजत ने कहा कि मेगा ऑक्शन में मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया तो मैं निराश हो गया था। डर था कि मेरा आईपीएल में सिलेक्शन होगा कि नहीं। फिर मुझे रिप्लेसमेंट के रूप में पिक किया गया। दूसरा चांस मिलने पर बहुत कॉन्फिडेंट था कि जब मैं यहां तक आया हूं तो आगे भी जा सकता हूं। खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यहां कई लीजेंड्स को लीड करने का मौका मिलेगा। मैं बहुत कुशल तरीके से सभी को साथ लेकर कप्तानी करूंगा। मेरा सफर काफी ऊपर-नीचे रहा है। खुद पर भरोसा करता हूं, यही मेरी ताकत है और आगे भी रहेगी।

हिंसा प्रभावित मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन, बीजेपी को नहीं मिला नया मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। यह कदम मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा रविवार को अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। सिंह का यह फैसला पूर्वोत्तर प्रांत में जातीय हिंसा के लगभग 21 महीने बाद आया था, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस दौरान हजारों लोग विस्थापित भी हुए हैं। राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता और सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से अब तक नए नेता के बारे में फैसला नहीं लेने के बीच यह कदम उठाया गया। राज्यपाल अजय भल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मणिपुर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट तथा प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के बाद स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य की सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है। बता दें कि इससे पहले संबित पात्रा के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की थी। 9 फरवरी को हिंसा से प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद नेतृत्व संकट पैदा हो गया था।

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों ने गुरुवार को ही राजभवन में बैठक की थी। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती और परिचालन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बयान में कहा गया कि मणिपुर और नगालैंड सेक्टर के निवर्तमान महानिरीक्षक (सीआरपीएफ) डॉ. विपुल कुमार और नवनियुक्त महानिरीक्षक राजेंद्र नारायण दाश ने राज्यपाल से मुलाकात की। इसमें कहा गया कि अधिकारियों ने राज्यपाल को क्षेत्र में सीआरपीएफ की तैनाती और परिचालन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

बता दें कि दिसंबर 2024 में मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और उसमें हुई जनहानि को लेकर माफी मांगी थी। बीरेन सिंह ने कहा था कि पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इसका मुझे बहुत दुख है। 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए मैं राज्य के लोगों से माफी मांगता हूं।

गुजरात में सड़क हादसा, जैन आर्यिका श्रुतमति माताजी और एक श्रावक का निधन

दाहोद/इंदौर। गुजरात के दाहोद में एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना में जैन आर्यिका श्रुतमति माताजी और एक श्रावक का तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से निधन हो गया। यह घटना गुरुवार सुबह करीब 7 बजे की है, जब माताजी विहार कर रही थीं। घटना की भयावहता इस बात से स्पष्ट होती है कि टक्कर के बाद वाहन ने माताजी को लगभग 300 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। माताजी मुंबई से आचार्य भगवंत के दर्शन के लिए विहार कर रही थीं और मात्र 36 वर्ष की थीं। इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिलते ही जैन समाज में गहरा शोक और आक्रोश फैल गया। आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की और कड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि जब तक दोषी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, वे किसी भी प्रकार का आहार या जल ग्रहण नहीं करेंगे। जैन समाज के प्रमुख संगठनों ने इस घटना पर तीव्र नाराजगी जाहिर की है। वीर जिनशासन एकता संघ के प्रचारक राजेश जैन दद्दू और विश्व जैन संगठन के मयंक जैन ने गुजरात सरकार से मांग की है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जैन समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस घटना के बाद समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है और देशभर के जैन अनुयायी न्याय की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आर्यिका श्रुतमति माताजी, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज से शिक्षित थीं और आचार्य सुनीलसागर जी की शिष्या थीं। इस हृदयविदारक हादसे से न केवल गुजरात बल्कि इंदौर सहित पूरे देश के समूचे जैन समाज में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई है।

मुकेश अंबानी का परिवार एशिया के सबसे अमीर परिवारों में नंबर वन

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी जिन्हें भारत के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है, के परिवार को एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में पहला स्थान मिला है। ब्लूमबर्ग द्वारा गुरुवार को जारी की गई इस लिस्ट में अंबानी परिवार के अलावा कुछ और भारतीय परिवार भी शामिल हैं। आपको बता दें, मुकेश अंबानी ने 2002 में अपने पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद रिलायंस की कमान संभाली थी और तब से उन्होंने इस ग्रुप को वैश्विक स्तर का बिजनेस ग्रुप बना दिया है। आज रिलायंस इंडस्ट्री का दबदबा तेल रिफाइनिंग, टेक, रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी का परिवार इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। दरअसल, यह लिस्ट केवल उन परिवारों को शामिल करती है, जिनकी पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। गौतम अडानी एक फर्स्ट-जनरेशन बिजनेसमैन हैं, इसलिए उन्हें इस डायनास्टिक-स्पेसिफिक रैंकिंग से बाहर रखा गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, यह रैंकिंग 31 जनवरी 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें फर्स्ट-जनरेशन वेल्थ (जैसे अलीबाबा के जैक मा और भारत के गौतम अडानी) की संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है।

लिस्ट में ये भारती परिवार भी शामिल *ब्लूमबर्ग द्वारा गुरुवार को जारी की गई इस लिस्ट में अंबानी परिवार के अलावा अन्य भारतीय परिवार भी शामिल हैं। इसमें मित्तल परिवार (शापूरजी पालोनजी ग्रुप) भी शामिल है। 1865 में स्थापित यह परिवार टाटा सन्स में अपनी हिस्सेदारी के लिए जाना जाता है, जो 400 बिलियन डॉलर के टाटा ग्रुप का हिस्सा है. नोएल टाटा फिलहाल टाटा ट्रस्ट्स का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा जिंदल परिवार (ओपी जिंदल ग्रुप) भी इस लिस्ट में है। 1952 में एक स्टील प्लांट से शुरुआत करने वाले इस परिवार ने ऊर्जा, सीमेंट और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में अपना साम्राज्य फैलाया है। ओपी जिंदल की पत्नी सावित्री और उनके चार बेटे अब इस ग्रुप को आगे बढ़ा रहे हैं। बिरला परिवार (आदित्य बिड़ला ग्रुप) भी इस लिस्ट में शामिल है। 19वीं सदी से अपनी विरासत को संभाल रहे इस परिवार का मेटल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल जैसे क्षेत्रों में बड़ा योगदान है। कुमार मंगलम बिड़ला फिलहाल इस ग्रुप के प्रमुख हैं। इनके अलावा बजाज परिवार (बजाज ग्रुप) भी इस लिस्ट में है। 1926 में जमनालाल बजाज द्वारा स्थापित इस ग्रुप ने स्कूटर बनाने से शुरुआत की और आज सीमेंट, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। राहुल बजाज अब इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं। हिंदुजा परिवार (हिंदुजा ग्रुप) को भी लिस्ट में स्थान मिला है। 1914 में ट्रेड और बैंकिंग से शुरुआत करने वाले इस परिवार का अब ऊर्जा, ऑटोमोटिव, फाइनेंस और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रभाव है।*

एशिया के टॉप 20 अमीर परिवारों की लिस्ट *अंबानी - रिलायंस इंडस्ट्रीज (भारत), चियारावनोंट - चारोन पोकफंड ग्रुप (थाईलैंड), हार्टोनो - डजारुम, बैंक सेंट्रल एशिया (इंडोनेशिया), मिस्त्री - शापूरजी पालोनजी ग्रुप (भारत), क्रोक - सन हंग काई प्रॉपर्टीज (हांगकांग), त्साई - कैथे फाइनेंशियल, फूबॉन फाइनेंशियल (ताइवान), जिंदल - ओपी जिंदल ग्रुप (भारत), यूविध्या - टीसीपी ग्रुप (थाईलैंड), बिरला - आदित्य बिरला ग्रुप (भारत), ली - सैमसंग (दक्षिण कोरिया), झांग - चाइना होंगकियाओ, शैंडोंग वेइकियाओ टेक्सटाइल (चीन), चेंग - न्यू वर्ल्ड डेवलपमेंट, चाउ टाई फूक (हांगकांग), बजाज - बजाज ग्रुप (भारत), पाओ/वू - बीडब्ल्यू ग्रुप, व्हीलॉक (हांगकांग), क्रेक/क्यूक - हांग लियोंग ग्रुप (सिंगापुर/मलेशिया), कदूरी - सीएलपी होल्डिंग्स (हांगकांग), चिरथिवत - सेंट्रल ग्रुप (थाईलैंड), हिंदुजा - हिंदुजा ग्रुप (भारत), सिस - एसएम इन्वेस्टमेंट्स (फिलीपींस), ली - ली कुम की (हांगकांग)।*

इंदौर में उतरेंगे 15 प्राइवेट जेट, उद्योगपतियों के स्वागत के लिए तैयार सबसे स्वच्छ शहर

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में गुरुवार को इंदौर के रेसीडेंसी सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों की संयुक्त कार्यशाला इंदौर संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हुए उनसे आग्रह किया गया कि वे बड़ी संख्या में इस समिट में भाग लें और अधिक से अधिक निवेश करें। सभी ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है, जहां बेहतर सुविधाएं और संसाधन मौजूद हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि 15

प्राइवेट जेट इंदौर एयरपोर्ट पर आएंगे जिसमें देश के शीर्ष उद्योगपति होंगे। उनके स्वागत के लिए इंदौर तैयार है।

इस कार्यशाला में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, उषा ठाकुर, मधु वर्मा तथा गोलू शुक्ला, कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, एमपीआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश राठौर, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.पी. अहिरवाल, सुमित मिश्रा, श्रवण चावड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट वातावरण

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-विकसित मध्यप्रदेश संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश तीव्र गति से औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट वातावरण है और राज्य सरकार हर स्तर पर निवेशकों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे इन्वेस्ट समिट में भाग लें और अधिक से अधिक निवेश करें, राज्य शासन उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगा और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

एआई को प्राथमिकता देना जरूरी

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इन्वेस्ट समिट औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने का एक शानदार प्रयास है। उन्होंने आईटी, माइक्रो चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेक्टर को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता जताई और कहा कि इनके लिए अलग से भी एक समिट आयोजित की जा सकती है। उन्होंने निवेशकों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए परामर्शदाता और सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इंदौर में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और यह औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान है। उन्होंने क्षेत्रीय विकास और निवेश योजना (मेट्रोपॉलिटिन एरिया) के बारे में भी जानकारी दी और उद्योगपतियों के सुझाव मांगे। उन्होंने बताया कि यह योजना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप बनाई जा रही है, जिससे इंदौर और उज्जैन संभाग को मिलाकर एक सुव्यवस्थित और समग्र विकास की रणनीति तैयार की जा सके।

इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश में विभिन्न आर्थिक मापदंडों, सड़क और वायुमार्ग की कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक हब, प्रस्तावित कॉरिडोर्स, मध्यप्रदेश इंडस्ट्रीयल इको-सिस्टम, पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों, इंदौर के औद्योगिक परिदृश्य, यहां उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों, औद्योगिक नीतियों, प्रस्तावित नीतियों, इंदौर संभाग में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही, 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में भी चर्चा की गई। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मधुमिलन चौराहे के यातायात प्लान की प्रस्तावित योजना की भी जानकारी साझा की गई।

शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को राहत, हाईकोर्ट ने लाटरी प्रक्रिया पर लगाई रोक

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के शिवाजी मार्केट में वर्षों से व्यापार कर रहे दुकानदारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शहर प्रशासन द्वारा इन दुकानदारों को नंदलालपुरा कॉम्पलेक्स में शिफ्ट करने के लिए चलाई गई लाटरी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से फिलहाल इन व्यापारियों को राहत मिली है, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। सरकार ने कान्ह नदी किनारे स्थित शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को रिवर साइड योजना के तहत विस्थापित करने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत दुकानदारों को कान्ह नदी के दूसरी ओर नंदलालपुरा कॉम्पलेक्स में स्थानांतरित किया जाना था। नगर निगम ने इस प्रक्रिया के तहत 10 फरवरी को लाटरी निकालकर दुकानों का आवंटन करना शुरू कर दिया था। लेकिन शिवाजी मार्केट के 69 दुकानदारों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपना विरोध दर्ज कराया।

5,000 लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है

दुकानदारों ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि वे पिछले 30 वर्षों से इसी स्थान पर व्यापार कर रहे हैं, और इस मार्केट से करीब 5,000 लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है।

उनका कहना था कि मुख्य सड़क से हटाकर उन्हें कॉम्पलेक्स में भेजने से उनका व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा, जिससे उनकी आजीविका पर संकट आ सकता है। इसके अलावा, याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि नगर निगम ने इस प्रक्रिया को अपनाने से पहले न तो एनओसी ली और न ही एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की अनुमति प्राप्त की। दुकानदारों का आरोप था कि बिना उचित सुनवाई के जबरन हटाया जाना अन्यायपूर्ण है और यह उनके जीविकोपार्जन के अधिकार का उल्लंघन है।

निगम आयुक्त को जारी किया नोटिस

तर्कों पर विचार करते हुए जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने नगर निगम आयुक्तऔर डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी किया और लाटरी प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया। इस फैसले से शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को फिलहाल राहत मिली है, और अब मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

सराफा व्यापारी की पत्नी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर की 9 साल पुरानी चर्चित राजकुमारी कटारिया मर्डर में जिला कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्यारे ने लूट की नीयत से सराफा व्यापारी के घर में घुसकर उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। आरोपी का नाम सोनू पिता रामप्रसाद (41), निवासी इंदौर है। यह वारदात 31 मई 2016 को बैकुंठधाम कॉलोनी में हुई थी। घटना के समय राजकुमारी कटारिया घर में अकेली थीं, तभी हत्यारे ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और घटनास्थल से शर्ट के तीन बटन सहित अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र किए। जांच के दौरान पुलिस ने नजदीकी लोगों के बयान लिए और संदेह के आधार पर सोनू को पकड़ा तो उसने पहले टालमटोल की। फिर कबूला कि, वह लूट की नीयत से राजकुमारी के घर तब गया। जब

वह दिन में वह अकेली थी। राजकुमारी द्वारा विरोध करने पर उसने उनकी हत्या कर दी थी। पूछताछ में आरोपी सोनू द्वारा शर्ट और घटना में प्रयुक?त गुप?ती नाले में फेंकना बताया, जिसे पुलिस ने जब्त किया। इसका खुलासा पुलिस ने 8 जून 2016 को किया था। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया। 11 फरवरी को कोर्ट ने आरोपी सोनू को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और धारा 394 सहपठित धारा 398 भा में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गोकुल सिंह सिसोदिया द्वारा की गई। खास बात यह कि, घटना जघन?य और सनसनीखेज होने से प्रकरण को चिह्नित सनसनीखेज अपराध की सूची में शामिल किया गया था। अभियोजन की ओर से प्रस?तुत रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण की समीक्षा हर माह की गई। केस में एक अन?य आरोपी सचिन को आरोपों से दोषमुक?त किया गया।

परम पूज्य गुरुदेव आदित्य सागर जी महाराज के विहार में दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ने लिया मंगल आर्शीवाद

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर, मुनि आदित्य सागर जी महाराज का भोपाल से इंदौर के लिए विहार चल रहा है गुरुवार को मुनि संघ ने पुष्पगिरी गिरी से देवास की ओर विहार किया देवास प्रेस्टिज फार्म हाउस पहुंचने पर युवा प्रोकोष्ट के पदाधिकारी

द्वारा गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया विहार के दौरान गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ इस अवसर पर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महावीर जैन , नीरज जैन अखिलेश जैन, सौरभ जैन एनकांउटर न्यूज के सुदेश गुप्ता उपस्थित थे।

नगर निगम अब मोबाइल एप से अफसरों की लोकेशन करेगा ट्रैक

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर नगर निगम अब अपने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नजर रखने के लिए तकनीक का उपयोग करने जा रहा है। इसके तहत एक विशेष मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, जिससे अधिकारियों की रियल-टाइम लोकेशन निगम के सिस्टम में दर्ज होगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों को और अधिक प्रभावी बनाना है। फिलहाल नगर निगम के अधिकारी अलग-अलग क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं, और उन्हें सुबह जल्दी अपने निर्धारित क्षेत्रों का दौरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ अधिकारी भ्रमण के दौरान गलत लोकेशन रिपोर्ट कर रहे थे। वे मोटोरोला सेट के माध्यम से अपनी उपस्थिति एक स्थान पर दिखाते थे, जबकि वास्तव में किसी अन्य स्थान पर होते थे। इस समस्या को समाप्त करने के लिए अब निगम ने नई तकनीक अपनाने का फैसला किया है। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि निगम ने मोटोरोला सेट प्रदान करने वाली कंपनी के साथ एक नया एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत निगम अधिकारियों के मोबाइल में इस कंपनी का विशेष एप डाउनलोड कराया जाएगा। यह एप अधिकारी की वास्तविक लोकेशन को रियल-टाइम में ट्रैक करेगा और नगर निगम के सिस्टम में दर्ज करेगा।

इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिकारी सुबह कितने बजे दौरे के लिए निकले और किस क्षेत्र में कब पहुंचे।इस सिस्टम के विकास पर नगर निगम द्वारा 20 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं, और इसे जल्द ही लागू करने की योजना बनाई गई है। निगम के अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि इस नए सिस्टम में जब कोई अधिकारी अपनी लोकेशन रिपोर्ट करेगा, तो वह जानकारी ऑटोमैटिक रूप से वायरलेस सेट पर भी सभी को सुनाई देगी। इससे निगरानी की दोहरी व्यवस्था लागू होगी और स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

नगर निगम ने बनाई छह नए फायर स्टेशन बनाने की योजना, बढ़ेगी फायर सेफ्टी

इंदौर। इंदौर शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और विस्तार को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए छह नए फायर स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। इनमें से दो फायर स्टेशन इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) द्वारा बनाए जाएंगे, जबकि शेष चार फायर स्टेशन नगर निगम के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, फायर फाइटर्स को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने की भी योजना है, ताकि वे आग की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पा सकें और शहर को सुरक्षित बना सकें। इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के मुताबिक आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए शहर की बहुमंजिला इमारतों की नियमित रूप से जांच की जाती है और उन्हें अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी उपकरण लगाने के निर्देश दिए जाते हैं। यदि निर्धारित समय में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता, तो संबंधित बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में, शहर में इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके।

आयुक्त वर्मा ने यह भी बताया कि वर्तमान में शहर में केवल पांच फायर स्टेशन कार्यरत हैं, जो तेजी से बढ़ते इंदौर की जरूरतों

को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए छह नए फायर स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से दो फायर स्टेशन आईडीए और चार नगर निगम द्वारा तैयार किए जाएंगे।

इसके अलावा, शहर की ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए आधुनिक उपकरण भी खरीदे जाएंगे। इस संबंध में फायर फाइटर्स के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनकी आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। फायर फाइटर्स ने अपनी जरूरतों में लाइट माउंटेड हेलमेट सहित अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की मांग की है, ताकि वे किसी भी आगजनी की घटना में बेहतर और सुरक्षित तरीके से काम कर सकें। नगर निगम जल्द ही इन उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करेगा, जिससे फायर फाइटिंग टीम और अधिक प्रभावी रूप से काम कर सके।

गर्मी में बढ़ जाती हैं आग की घटनाएं

मोती तबेला फायर स्टेशन के रिनोवेशन का भी फैसला लिया गया है। आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए सभी फायर स्टेशनों को पूरी तरह तैयार रखना आवश्यक है। मोती तबेला फायर स्टेशन में नए उपकरणों की जरूरत है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। नगर निगम ने यह भी घोषणा की है कि बड़ी इमारतों और स्कूलों में नियमित मॉक ड्रिल्स आयोजित की जाएंगी, जिससे नागरिकों को फायर सेफ्टी उपकरणों का सही इस्तेमाल सिखाया जा सके और किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे तेजी से प्रतिक्रिया दे सकें।

एयरपोर्ट पर 1 अप्रैल से होगा बड़ा बदलाव, आठ घंटे तक बंद रहेंगी उड़ानें

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय विमानतल 1 अप्रैल से रात 10.30 बजे से सुबह 6.30 बजे के बीच बंद रहेगा। इस दौरान रनवे क्लोजर के कारण उड़ानों का संचालन नहीं हो पाएगा और इस समय में संचालित होने वाली 14 उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए सभी एयरलाइंस को जानकारी दी है। यह बदलाव रनवे की मरम्मत के लिए किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत फरवरी से होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे जनवरी में शुरू नहीं किया जा सका था। अब यह कार्य 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें रात 12 से सुबह 6 बजे के बीच एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन बंद रहेगा।चूंकि यह कार्य शुरू करने में देरी हो चुकी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से यह काम रात 10.30 बजे से सुबह 6.30 बजे के बीच किया जाएगा। इससे पहले केवल 6 घंटे तक उड़ानें प्रभावित हो रही थीं, लेकिन अब 8 घंटे तक एयरपोर्ट बंद रहेगा। एयरपोर्ट प्रबंधन ने सभी एयरलाइंस से अनुरोध किया

है कि इस अवधि के दौरान जो उड़ानें संचालित हो रही हैं, उन्हें 1 अप्रैल से 10.30 बजे से पहले या सुबह 6.30 बजे के बाद शेड्यूल किया जाए। इस बदलाव के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस की शारजाह उड़ान सहित इंडिगो की दिल्ली, जयपुर, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु और पुणे की 12 अन्य उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। एयरलाइंस को यह परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके लिए अपनी उड़ानों का समय बदलना मुश्किल होगा। इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से रात 10.30 के बजाय रात 12 बजे तक उड़ानों के संचालन की छूट भी मांगी है। इंदौर एयरपोर्ट के रनवे की मरम्मत के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सितंबर में टेंडर जारी किए थे और नवंबर में 25 करोड़ रुपए की लागत से यह काम श्रीसांई कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था। इस काम में रनवे पर डामर की परत को हटाकर नई 8 इंच मोटी परत डाली जाएगी। यह काम रात के समय में होगा, जिससे उड़ानों का संचालन रुक जाएगा। इस मरम्मत कार्य को एक साल में पूरा करने की योजना है। वर्तमान में 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक के लिए रात 10.30 से सुबह 6.30 बजे तक रनवे क्लोजर का आदेश जारी किया गया है, और नवंबर से मार्च तक भी इसे जारी किया जा सकता है।

सिंधिया और नरोत्तम की मुलाकात से तेज हुई प्रदेश अध्यक्ष की अटकलें

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। मध्यप्रदेश में जिला भाजपा अध्यक्षों के नामों का एलान होने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम की जल्द घोषणा हो सकती है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल मंगु भाई पटेल, मंत्री करण सिंह वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उनके निवास पर मुलाकात की। नरोत्तम मिश्रा से उनकी मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि, नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात के बाद बयान दिया कि वे किसी दौड़ में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी काम देती रहे, बस यही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई।

मिश्रा ने कहा कि मंडल और जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो चुका है और प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी जल्द घोषित होगा, लेकिन इसका फैसला दिल्ली में होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे नेता हैं, वो समय समय पर आते रहते हैं।

ये पारिवारिक मुलाकातें हैं

वहीं, सिंधिया ने कहा कि यह पारिवारिक मुलाकातें हैं, जैसे आप अपने परिवार से मिलते हैं, वैसे ही मैं अपने परिवार के लोगों से मिलता हूं। बता दें भाजपा के संगठन चुनाव में 65 हजार बूथ समितियों का गठन किया जा चुका है। अब तक 1300 मंडल अध्यक्षों में से लगभग 1100 मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और सभी 62 जिला अध्यक्षों के चुनाव भी हो चुके हैं।

हेमंत खंडेलवाल सबसे मजबूत दावेदार

मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हेमंत खंडेलवाल को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हेमंत खंडेलवाल के संघ से जुडे होने और विवादों से दूर रहने के चलते पार्टी अब धीरे धीरे उनके नाम पर सहमति बना रही है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल पांच साल का हो चुका है और उन्हें फिर से मौका मिलने की संभावना कम है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए हेमंत खंडेलवाल पहली पसंद बन गए हैं। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी जातिगत समीकरणों को साधना चाहेगी। ऐसे में संभावना है कि नया अध्यक्ष सामान्य, आदिवासी या महिला वर्ग से हो सकता है, क्योंकि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद डिप्टी सीएम और मंत्रियों के लिए भी जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा था। अभी अध्यक्ष पद की रेस में कई सीनियर नेता भी दावेदार हैं। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा सीनियर नेता को कमान सौंपती है या फिर किसी नए चहेरे पर दांव लगाती है।

नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी भी मजबूत

पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। वह सवर्ण वर्ग से आते हैं और राज्य की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। उनकी केंद्रीय नेतृत्व से भी अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती है।

आदिवासी वर्ग से आते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी वर्ग से आते हैं और मध्यप्रदेश में आदिवासी वर्ग की अहमियत को देखते हुए उनकी दावेदारी काफी मजबूत हो सकती है।

वीडी शर्मा का नाम भी रेस में

वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम भी रेस में हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी एक बार फिर उनके नाम पर विचार कर सकती है।

कुशल रणनीतिकार हैं अरविंद भदौरिया

पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया संगठन के एक कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। हालांकि, वह 2023 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन पार्टी उन्हें एक बार फिर सक्रिय करना चाहती है।

फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए

कद से ज्यादा बड़ी हैं अफसरों की सरकारी गाड़ियां!

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार सरकारी अफसरों के गाड़ियों के शौक पर लगाम लगाने की तैयारी में है। कई अफसर एक से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ तो नियम तोड़कर महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने नए नियम बनाए हैं। अफसर अब एक से ज्यादा गाड़ी नहीं रख पाएंगे। सरकार सभी गाड़ियों का रिकॉर्ड भी मांग रही है। यह सब कब और कैसे होगा, यह भी बताया गया है।

मध्य प्रदेश में सरकारी अफसरों के लिए गाड़ियों के नियम पहले से तय हैं।

लेकिन कई अफसर इन नियमों को नहीं मान रहे हैं। इसकी शिकायतें सरकार को मिली हैं। सरकार ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि नियमों का पालन करें। अब देखना होगा कि अफसर इन नए नियमों का कितना पालन करते हैं। सरकार को मिली शिकायतों में बताया गया है कि कई अफसर नियमों से ज्यादा महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ अफसरों के पास एक से ज्यादा सरकारी गाड़ियां हैं। इस फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के मुताबिक, अब कोई भी अफसर एक से ज्यादा सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सरकार ने सभी विभागों से गाड़ियों का रिकॉर्ड मांगा है। इससे पता चलेगा कि किस अफसर के पास कितनी गाड़ियां हैं और वे नियमों के मुताबिक हैं या नहीं। अगर कोई अफसर नियम तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे गाड़ियों के इस्तेमाल पर नजर रखें और

नियमों का सख्ती से पालन करवाएं।

ये हैं नियम

नियमों के अनुसार, 7600 ग्रेड पे वाले अफसर साढ़े छह लाख रुपए तक की गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8700 ग्रेड पे वालों के लिए आठ लाख और 9000 या उससे ज्यादा ग्रेड पे वालों के लिए दस लाख रुपये तक की गाड़ी की सीमा है। लेकिन कई अफसर इन नियमों को ताक पर रखकर महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे ज्यादा शिकायतें पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग के खिलाफ मिली हैं। इन विभागों में गाड़ियों के इस्तेमाल और उनके भुगतान की जानकारी मंगाई गई है। जल संसाधन विभाग ने तो गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

ये हैं आदेश

मीडिया से बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा कि विभाग के सभी अफसरों को गाड़ियों को लेकर नए निर्देश दिए गए हैं। अब टैक्सी कोटे की गाड़ियों का मालिक प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि ऐसा पाया गया तो भुगतान होने वाली राशि से दोगुनी राशि वसूल की जाएगी। साथ ही किराए की गाड़ी सरकारी ड्राइवर द्वारा नहीं चलाई जाएगी। निजी कामों में इस्तेमाल पर रोक इसके अलावा, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी कामों के लिए ही हो। अगर कोई अफसर निजी कामों के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल में पहली बार भीख लेने और देने वाले पर एफआईआर दर्ज

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। भीख मांगने और भीख देने पर एफआईआर दर्ज हुई है। यह पहली एफआईआर है। एमपी नगर थाने में यह मामला दर्ज किया गया। एक एनजीओ से जुड़े व्यक्ति ने शिकायत की थी। कलेक्टर ने शहर में भीख मांगने पर रोक लगाई है। इस आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई। भीख मांगने वाले और भीख देने वाले ट्रक ड्राइवर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। शिकायतकर्ता ने वीडियो बनाया था। उसी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। यह मामला बीएनएस की धारा 223 के तहत दर्ज किया गया है। यह धारा सरकारी आदेश की अवहेलना करने पर लागू होती है। जांच अधिकारी एसआई कुलदीप खरे ने बताया कि शिकायतकर्ता मोहन सिंह सोनी एक एनजीओ से जुड़े हैं। वे कलेक्टर द्वारा गठित टीमों का हिस्सा हैं। ये टीमें शहर में भीख मांगने वालों पर नजर रखती हैं। सोनी ने बताया कि वे अपनी टीम के साथ एमपी नगर के बोर्ड ऑफिस स्क्वायर से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक व्यक्ति को भीख मांगते और एक ट्रक चालक को उसे भीख देते देखा। उन्होंने घटना का वीडियो बनाया और एमपी नगर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस ने अज्ञात भिखारी और भीख देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो की मदद से पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कलेक्टर के आदेश के बाद यह पहला मामला है। इससे पहले भीख मांगने वालों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। यह आदेश शहर में भीख मांगने और भीख देने दोनों पर रोक लगाता है। इससे पहले भीख मांगने पर रोक तो थी, पर भीख देने पर कोई पाबंदी नहीं थी। इस नए आदेश के बाद, अब भीख देने वाले भी कानून के दायरे में आ गए हैं। अगर कोई व्यक्ति भीख मांगता या देता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बेगर फ्री सिटी की कवायद

यह कदम शहर में भीख मांगने की समस्या को कम करने के लिए उठाया गया है। कई लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे शहर की छवि सुधरेगी। साथ ही, यह भीख मांगने वालों को पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित करेगा। हालांकि, कुछ लोग इस कदम की आलोचना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों की समस्या बढ़ेगी। फिर भी, प्रशासन का मानना है कि यह कदम लंबे समय में शहर के लिए फायदेमंद साबित होगा। देखना होगा कि इस नए नियम का क्या असर होता है। क्या वाकई में शहर से भीख मांगने की समस्या कम होगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

रेंज रोवर ने 4 बाइकों को टक्कर मारी, पांच लोग घायल

भोपाल। भोपाल के चेतक ब्रिज पर गुरुवार दोपहर लगभग 12.30 बजे एक तेज रफ्तार रेंज रोवर कार (एमपी04 सीएन 5575) ने 4 बाइकों को टक्कर मार दी। इसके बाद कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 4-5 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। चालक को भी चोट आई थी। उसे भी अस्पताल भेजा गया है। घायल धर्मेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि कार सवार रॉन्ग साइड से आ रहा था और उसने पीछे से उनकी स्कूटी को टक्कर मारी। इसके बाद कार ने कुछ और वाहनों को भी टक्कर मारी और आखिर में डिवाइडर से टकराकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार में दो लोग सवार थे। डिवाइडर से टकराने के बाद ड्राइवर ने उल्टियां भी कीं। दुर्घटना के बाद चेतक ब्रिज पर दोनों लेन में लंबा जाम लग गया। करीब 45 मिनट तक गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को क्लियर किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के बाद 108 नंबर से एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन लगभग 40-45 मिनट की देरी से एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। इस बीच लोग घायलों को अस्पताल पहुंचा चुके थे। वहीं, ट्रैफिक पुलिस भी हादसे में क्षतिग्रस्त गाड़ी को मौके से हटा चुकी थी। एम्बुलेंस ड्राइवर से देरी के सवाल पर पूछा तो कहा गया कि वो बैरसिया से आए हैं। आस-पास की गाड़ियां पहले ही कॉल पर हैं।

जयंत मलैया अब शिष्टाचार और सम्मान अनुरक्षण संबंधी समिति के सभापति होंगे

भोपाल। पूर्व वित्त मंत्री और दमोह विधायक जयंत मलैया अब विधायकों के शिष्टाचार और सम्मान अनुरक्षण संबंधी समिति के सभापति होंगे। विधायक मलैया को विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी नामांकित सदस्यों और सभापतियों की सूची में सभापति बनाया गया है। इसके पहले इस समिति के सभापति पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और इटारसी विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा थे जिन्होंने समिति से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा सचिवालय के अनुसार विधानसभा की वर्ष 2024-25 की अवधि में सेवा करने के लिए गठित सदस्यों के शिष्टाचार एवं सम्मान अनुरक्षण समिति में सभापति का पद रिक्त था। इस रिक्त स्थान पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जयंत मलैया विधायक को नामांकित करने का निर्णय लिया है। इसलिए विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन मलैया को सभापति नियुक्त किया गया है। सभापति का यह पद 12 सितम्बर 2024 को पूर्व सभापति डॉ सीतासरन शर्मा द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण रिक्त था। सदस्यों के शिष्टाचार और सम्मान अनुरक्षण समिति में सभापति को नामांकित किए जाने के बाद अब समिति में जयंत मलैया सभापति होंगे। जबकि विधायक रमेश मेंदोला, अनिल जैन निवाड़ी, शरद जुगलाल कोल, राजकुमार करहें, प्रताप ग्रेवाल और भंवर सिंह शेखावत सदस्य के रूप में काम करेंगे। गौरतलब है कि इसके अलावा विधानसभा की याचिका और अभ्यावेदन समिति के सभापति हरदीप सिंह डंग, नियम समिति के सभापति मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति संजय पाठक, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति हरिशंकर खटीक, पुस्तकालय, अनुसंधान और संदर्भ समिति के सभापति ओमपकाश सखलेचा, आचरण समिति के सभापति सरेंद्र पटवा, पटल पर रखे गए पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति के सभापति ओमप्रकाश धुर्वे, प्रश्न और संदर्भ समिति के सभापति बृजेंद्र प्रताप सिंह, कृषि विकास समिति के सभापति दिलीप सिंह परिहार तथा महिला और बाल कल्याण समिति के सभापति अर्चना चिटनिस हैं।

पूर्व विधायक के पोते ने की खुदकुशी,भाई-बहन ने फंदे पर लटका देखा

भोपाल। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में रहने वाले 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। घटना बुधवार की देर रात की है। पुलिस ने गुरुवार की दोपहर को पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक पूर्व विधायक नरेशसिंह पटेल का पोता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी बृजेंद्र निगम ने बताया कि, छात्र के पिता का निधन काफी समय पहले हो चुका है। घर में मां, बड़ा भाई और छोटी बहन है। बुधवार रात छात्र अंदर वाले कमरे में था और बाकी सदस्य बाहर के कमरे में बातें कर रहे थे। इस बीच छात्र ने रस्सी से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। छात्र काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया। भाई-बहन उसे बुलाने पहुंचे। कमरे का गेट खोलते ही उन्हें भाई का शव फंदे पर लटका मिला। यह देख उनकी चीख निकल गई। दौड़कर आई मां बेटे को फंदे पर लटका देख बेसुध हो गई। चीखों की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया, यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि, छात्र के गुमसुम रहने की बात सामने आई है।

रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा को रिटायरमेंट के 11 दिन बाद मिला काम

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। मध्यप्रदेश कैडर के एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को सेवानिवृत्ति के 11 दिन बाद ही सरकार ने काम पर रख लिया। मामला रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा से जुड़ा है। 31 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए एसएन मिश्रा गृह विभाग के एसीएस थे, लेकिन उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया था। इसके बाद बुधवार को अचानक सरकार ने सरप्राइज देते हुए एन.एन. मिश्रा को प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का सदस्य बना दिया।गौरतलब है कि 31 जनवरी को अपर मुख्य सचिव गृह और परिवहन विभाग के पद से रिटायर एसएन मिश्रा पर डॉ. मोहन यादव सरकार ने फिर भरोसा जताया है। रिटायरमेंट के 11 दिन बाद राज्य शासन ने मिश्रा को प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के सदस्य की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।एस एन मिश्रा रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव की जगह लेंगे। मनोज श्रीवास्तव को सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया था। सरकार ने करीब सवा महीने के अंतराल के बाद मध्य प्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन

आयोग के पद पर नए सदस्य के रूप में एसएन मिश्रा की नियुक्ति की है।

कई जरूरी कामों में आएगी तेजी

एस एन मिश्रा अब प्रदेश में नए जिलों, संभागों, तहसीलों, जनपदों और अन्य प्रशासनिक सीमाओं के गठन को लेकर अफसरों, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों से सुझाव लेकर राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। संभावना है कि राज्य में धीमी पड़ी प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की बैठकों की कार्रवाई अब तेज होगी। जनगणना का काम 30 जून तक चलने की स्थिति को देखते हुए चार माह में प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की संभावना तेज हो गई है।

जल्द ही नए सचिव की नियुक्ति

इससे पहले प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के सदस्य के तौर पर पूर्व एसीएस मनोज श्रीवास्तव ने कई संभागों में बैठक कर लोगों से सुझाव भी लिए थे। इसके बाद आयोग के एक अन्य सदस्य और रिटायर्ड आईएएस मुकेश कुमार शुक्ला अपने स्तर पर जिलों में बैठकें ले रहे थे। संभावना है कि जल्दी ही आयोग के नए सचिव की नियुक्ति की जा सकती है।

सम्पादकीय

'मेड इन मप्र, ब्रांड को विश्व बाजार में चमकाएगी नई निर्यात नीति

मध्यप्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मोहन यादव कैबिनेट ने 'मध्यप्रदेश निर्यात नीति-2025' को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के निर्यात को बढ़ाना, निर्यात दक्षता में सुधार करना और 'मेड इन मध्यप्रदेश' ब्रांड को वैश्विक बाजार में स्थापित करना है। नीति के तहत मध्यप्रदेश में बड़े निर्यातकों की भागीदारी बढ़ाने, निर्यात डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने और निर्यातकों को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वृहद श्रेणी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उसके उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक निर्यात करने पर निर्यात प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मध्यप्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मोहन यादव कैबिनेट ने 'मध्यप्रदेश निर्यात नीति-2025' को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के निर्यात को बढ़ाना, निर्यात दक्षता में सुधार करना और 'मेड इन मध्यप्रदेश' ब्रांड को वैश्विक बाजार में स्थापित करना है। नीति के तहत मध्यप्रदेश में बड़े निर्यातकों की भागीदारी बढ़ाने, निर्यात डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने और निर्यातकों को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वृहद श्रेणी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उसके उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक निर्यात करने पर निर्यात प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें पहली बार निर्यात करने वाली यूनिट के लिए रजिस्ट्रेशन को मेंबरशिप सर्टिफिकेशन पर 10 लाख रुपए तक रीइम्बर्स्मन्ट और निर्मात बीमा प्रीमियम पर अधिकतम 25 लाख रुपए तक का रीइम्बर्स्मन्ट किया जाएगा। इसके अलावा निर्यात भाड़ा सहायता के रूप में फैक्टरी परिसर से बंदरगाह या एयर कार्गो या अंतरराष्ट्रीय सड़क मार्ग तक माल ले जाने के लिए किए गए खर्च की 50 प्रतिशत राशि और अधिकतम 2 करोड़ रुपए रीइम्बर्स्मन्ट किया जाएगा। निर्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता के तहत परीक्षण लैब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र, निर्यात इनक्यूबेशन केंद्र आदि एक्स्पोर्ट ओरिएंटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किए गए खर्च का 25 प्रतिशत अधिकतम 1 करोड़ रुपएतक की सरकार मदद करेगी। मध्यप्रदेश से निर्यात करने वाली इकाई के लिए इन्क्रीमेंटल फ्री ऑनबोर्ड वेल्यू (एफओबी) पर 10 प्रतिशत की सहायता 5 वर्षों तक अधिकतम 2 करोड़ रुपए निर्यात टर्नओवर सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। निर्यात विपणन सहायता मे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और केता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए खर्च का 75 प्रतिशत रीइम्बर्स्मन्ट अधिकतम 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। निर्यात ग्रीन दस्तावेज सहायता के रूप में निर्यात डाक्यूमेंट लागत (सीबीएएम, नेट-जीरो उत्सर्जन कार्बन ऑफसेटिंग आदि) पर किए गए खर्च का 50 फीसदी रीइम्बर्स्मन्ट अधिकतम 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति इकाई 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा। निर्यात वित्तीय सहायता में लिए गए लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। एचजीवी सेक्टर्स (फर्नीचर ट्रांसपोर्ट, आदि) एवं वैश्विक बाजार स्तर पर निर्यात की गई वस्तुओं (इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, अप्लाइन्स आदि) के लिए फ्री ऑनबोर्ड वेल्यू (एफओबी) के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता, अधिकतम 30 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 वर्ष की अवधि में निर्यात विकास संवर्धन प्रोत्साहन सहायता के रूप मे प्रदान की जाएगी। नई नीति के तहत कम से कम 25 एकड़ भूमि पर एक्स्पोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो पिछले तीन वर्षों में 25 प्रतिशत से अधिक उत्पादन निर्यात करती हैं, उन्हें डेडीकेटेड एक्सपोर्ट पार्क्स (डीईपी) में भाग लेने का अवसर मिलेगा। नीति में ग्रीन औद्योगीकरण को भी प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट और वॉटर पॉल्यूशन कंट्रोल जैसी सुविधाओं के लिए पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में निर्यात शुरू करने वाले स्टार्टअप्स के लिए एक्स्पोर्ट इनक्यूबेशन हब भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि उन्हें निर्यात प्रक्रिया में मार्गदर्शन और सहायता मिल सके। इसके अलावा प्रदेश के व्यापार सहायता कार्यक्रम, डिजिटल कॉमर्स, और ग्रीन कार्ड स्कीम से निर्यातकों को लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश निर्यात नीति-2025 अधोसंरचना में निजी डेवलपर्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए, निर्यात क्षेत्रों के डेवलपर्स को प्रोत्साहित करती है। नीति अंतर्गत प्रावधानित अन्य गैर-वित्तीय सहायता एवं आईसीडी को सुगम बनाने के निर्णयों से प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

यह कैसा हास्य जो रिश्तों को तार-तार कर दे

लोगों को कतई यह पता ही नहीं है कि एक युवा होना क्या होता है? वो नहीं जो महज गंदा मजाक करे और खींसें निपोरते नजर आए। हममें से कोई भी सच्चे दिल से अपने बच्चे को स्वामी विवेकानंद जैसा युवा बनाना चाहेगा। वो कतई समय रैना या रणवीर तो नहीं बनाना चाहेगा। ब्रिटिश राज में देश की आजादी के लिए जान देने वाले ज्यादातर क्रांतिकारी युवा ही थे, जो हंसे भी और हंसते हुए ही देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। स्टैंड अप कॉमेडियन उत्तम केवट भी यही मानते हैं कि अगर गंदी बात ही परोसी जाए तो यह सोशल मीडिया पर ज्यादा चलती है। लेकिन, हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कंटेंट परोसें जिसे पूरा परिवार मिलकर देखे और हंसे भी।

आप जरा सोचिए...आप जिस समाज में रह रहे हों, वहां अगर क्या हो कि हर कोई गाली देकर ही बात करता हो। राह चलते, बसों, मेट्रो या ट्रेनों में हर तरफ आपको गालियां ही सुननी पड़ रही हों... हमारी-आपकी मां-बहन या पत्नी को हर ओर ऐसी गालियों से दो-चार होना पड़ रहा है। क्या आप ऐसे मध्यकालीन सामंती युग में लौटना चाहेंगे। क्या हमारे या आप में से ही कोई दरिंदा पैदा हो जिससे हमारे घर-परिवारों की बहन-बेटियों को इस तरह की जिल्लत झेलनी पड़े। जाहिर है आप यह नहीं चाहेंगे। आप 21वीं सदी में जो हैं। मगर, कुछ लोगों के लिए यह सदी बस खुल्लमखुल्ला कुछ भी कह देने या कुछ भी सुना देने की सदी है। चाहे वो यू-ट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया हों या कॉमेडियन समय रैना। रणवीर ने एक शो में माता-पिता के अंतरंग संबंधों को लेकर टिप्पणी की थी। ऐसे लोगों को धिक्कार है, इन्हें आज की पीढ़ी का युवा कहते भी शर्म आती है।

इन लोगों को कतई यह पता ही नहीं है कि एक युवा होना क्या होता है? वो नहीं जो महज गंदा मजाक करे और खींसें निपोरते नजर आए। हममें से कोई भी सच्चे दिल से अपने बच्चे को स्वामी विवेकानंद जैसा युवा बनाना चाहेगा। वो कतई समय रैना या रणवीर तो नहीं बनाना चाहेगा। ब्रिटिश राज में देश की आजादी के लिए जान देने वाले ज्यादातर क्रांतिकारी युवा ही थे, जो हंसे भी और हंसते हुए ही देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। स्टैंड अप कॉमेडियन उत्तम केवट भी यही मानते हैं कि अगर गंदी बात ही परोसी जाए तो यह सोशल मीडिया पर ज्यादा चलता है। लेकिन, हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कंटेंट परोसें जिसे पूरा परिवार मिलकर देखे और हंसे भी। बच्चे को छिपकर वो कंटेंट न देखना पड़े और न ही उसे देखकर गलत या गंदी सोच पनपे। मिलियन व्यूज पाने की होड़ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? क्योंकि घूम-फिरकर के वही बातें समाज में गंदे रूपों में सामने आती हैं।

इन या किसी भी युवा को अगर असली हास्य देखना है तो महमूद और सुनील दत्त की फिल्म पड़ोसन, उत्पल दत्त की गोलमाल, धर्मेंद्र-अमिताभ की चुपके-चुपके जैसी फिल्में देखना चाहिए। आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। आज की कुछ फिल्में जैसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया, भागमभाग, धमाल जैसी भी हैं, जिन्होंने लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। मगर, रणवीर के जोक में आप सिर्फ खींसे निपोर सकते हैं, क्योंकि बाहर तो आप हंसने का नाटक कर सकते हैं, मगर भीतर आपको भी यह पता होता है कि यह आदमी हमारी सभ्यता को उघाड़ रहा है, उसे तार-तार कर रहा है।

पंजाब के गवर्नर को लंदन जाकर मारने वाले ऊधम सिंह को कौन नहीं जानता है। वे जलियांवाला बाग के हत्यारे जनरल माइकल ओ डायर की हत्या करने के बाद वहां से भागे नहीं। जब जज ने उनसे पूछा कि ऊधम सिंह तुम तो भाग सकते थे, भागे क्यों नहीं तो ऊधम सिंह ने कहा कि मैं भारत के युवाओं को यह मैसेज देना चाहता हूं कि मैं इसलिए फांसी चढ़ रहा हूं ताकि मेरे देश के युवा यह जानें कि देश के लिए जान कैसे दी जाती है? जाहिर है ये आत्ममुग्धता के शिकार, अपनी सभ्यता और संस्कृति का मजाक बनाने वाले और रील्स की दुनिया में खोए रणवीर और रैना जैसे निर्लज्ज युवाओं को तो कतई यह बात समझ नहीं आएगी। वो इसे भी मजाक बनाएंगे।

संविधान में भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 में वो सारे अधिकार दे दिए गए, जिसके लिए हमारे नायकों ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत देश के सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिले हैं। अगर कोई बाहर का यानी विदेशी नागरिक है तो उसे ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। वाक और अभिव्यक्ति की आजादी को आसान भाषा में समझे तो एक भारतीय नागरिक इस देश में लिखकर, बोलकर, छापकर, इशारे से या किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। वहीं, अनुच्छेद 19 (2) में उन नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई है जब बोलने की आजादी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। वे शर्तें हैं-कुछ भी ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो। राज्य की सुरक्षा को खतरा हो। पड़ोसी देश या विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बिगड़ने का खतरा हो। सार्वजनिक व्यवस्था के खराब होने का खतरा हो। शिष्टाचार या सदाचार के हित खराब हो। कोर्ट की अवमानना हो। किसी की मानहानि हो। अपराध को बढ़ावा मिलता हो। यही बोलने की हद है, जिसे हम सभी को समझना होगा और अपने बच्चों को भी सिखाना होगा। वैसे तो समाज में हर बात की प्रतिक्रिया होती है। मगर, सरकार को ऐसे एडल्ट कंटेंट पर भी नजर रखनी चाहिए कि इसके नाम पर कुछ भी नहीं परोसा जा सकता है। इसके लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 19 की शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी की बोलने की आजादी तभी तक होनी चाहिए, जब उससे समाज के दूसरे का अहित न हो। एक बाकायदा निगरानी तंत्र भी होना चाहिए, जो सोशल मीडिया पर पब्लिश होने से पहले उसकी 'छंटाई' करे।

समय रैना का 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो पहली बार विवादों में नहीं आया है। वह इससे पहले भी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए यह विवादों में रह चुका है। कॉमेडियन जेसी नबाम ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में अरुणाचल प्रदेश के लोगों के कुत्ते का मांस खाने के बारे में टिप्पणी की थी, जिसे लेकर जमकर विवाद हुआ था। इन टिप्पणियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए 31 जनवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा निवासी अरमान राम वेली बखा ने ईटानगर में एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं, इससे पहले एक अन्य शो में बालीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रेग्नेंसी और डिप्रेशन को मजाक बनाया गया था। इसके बाद समय रैना को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था।

फिल्मों या रचनाओं में गालियों का इस्तेमाल करने वाले यह तर्क देते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, जब वहां गालियों का इस्तेमाल आम बात है तो फिर इससे परहेज क्यों? ऐसे लोगों को यह समझना होगा कि फिल्में या रचनाएं भले समाज का आईना हैं, मगर ये उसी समाज को आईना भी दिखाती हैं। अगर हम गालियों और गंदे कंटेंट को ज्यादा तवज्जो देंगे तो इससे हमारी नई पीढ़ी के मन पर असर पड़ेगा। तब हमारे आपके ही बच्चों में से कोई नरपिशाच बन जाएगा जो किसी बेटी के साथ निर्भया जैसी बर्बरता करेगा। तब भी क्या हम उन गालियों को सही ठहराएंगे। गीतकार जावेद अख्तर ने एक शो 'चिल सेश' के तीसरे एपिसोड में कहा था कि गाली भाषा में मिर्च के समान है। उन्होंने कहा था कि ओडिशा, बिहार और मैक्सिको या दुनिया में और कहीं जहां भी गरीबी है, वहां के लोग बहुत सारी मिर्च खाते हैं। वहां का खाना फीका होता है ऐसे में टेस्ट को बढ़ाने के लिए वे मिर्च खाते हैं। गाली भाषा की मिर्ची है। अगर आपके जोक में दम नहीं है तो आप मिर्च यानी गाली का इस्तेमाल करोगे। वर्ना आपको इस मिर्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी। जावेद अख्तर की इस बात से बहुत हद तक सहमत हुआ जा सकता है। वे कहते हैं कि जब आपकी बातचीत नीरस है तो इसमें उर्जा देने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जो इंसान गाली देता है, इसका मतलब है कि उसे अपनी ही भाषा के शब्द नहीं आते हैं। उसके पास शब्दों की कमी है।

रणवीर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए कहा- मेरा कमेंट सही नहीं था और फनी भी नहीं था। कॉमेडी मेरी विशेषज्ञता नहीं है। मैं इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मैं बस सभी से माफी मांगना चाहता हूं। जो हुआ वह कूल नहीं था। परिवार की बेइज्जती मैं नहीं करूंगा। मैंने मेकर्स से कह दिया है कि विवादित टिप्पणी को हटा दिया जाए। मुझसे गलती हुई है। इंसानियत के नाते शायद आप मुझे माफ कर देंगे। मुझे इस प्लेटफॉर्म का और बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए था। यह मेरे लिए सबक है और मैं और बेहतर होने की कोशिश करूंगा।

कपिल शर्मा के शो पर शैलेश लोढ़ा ने एक बार कहा था जिस शो में दादी को बेवड़ी और बुआ को ठरकी दिखाकर पारिवारिक रिश्तों का मजाक उड़ाया जाता हो, वो हमारी संस्कृति को कहा ले जाएंगे। सभ्य हास्य का पतन इस शो से ही शुरू हुआ।

यह आकाशवाणी है...अब आप समाचार सुनिए...

यह आकाशवाणी है...अब आप समाचार सुनिए...। एक समय था जब यह अल्फाज रेडियो से निकलते थे तो नुक्कड़ की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते हुए लोगों में सन्नाटा छा जाता था। बुजुर्ग एक दूसरे को चुप होकर देश के हालात पर समाचार सुनने का इशारा करते थे तो सब शांत हो जाते थे। होली के सीजन में पहले से ही रेडियो पर उड़े रंग गुलाल और होली का त्योहार गांव-गांव में गूंजते फगुवा गीतों की बहार अलग ही आनंद देते थी। हर गांव-गली के चौपालों पर कृषि दर्शन, सैनिकों और किसान भाइयों के कार्यक्रम और रात में हवा महल का सभी को इंतजार रहता था, लेकिन अब रेडियो का जमाना गुजरे लंबे समय की बात हो चुकी है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिये फिर से रेडियो में जान फूंकने का काम जरूर किया है। लोगों का मानना है कि रेडियो की खबरों की गुणवत्ता और तथ्य एकदम सटीक होते थे। यह बहुत रोचक बात है लेकिन सत्य भी, गांव गांव में शादी-ब्याहों में भी रेडियो दहेज में दिया जाता था। जिसके घर रेडियो आता था, वह काफी प्रभावशाली माना जाता था। रेडियो हमेशा से ही लोगों का दोस्त रहा है। चाहे समय अच्छा हो या बुरा। जब से प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम शुरू हुआ ,रेडियो ने एक बार फिर सबके दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए हैं। भले ही इस कार्यक्रम ने एक लम्बा सफर तय किया है, लेकिन कई लोग अभी भी इस बात से हैरान हैं कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के लिए रेडियो को एक माध्यम के रूप में क्यों चुना । इसका कारण यह है कि रेडियो की व्यापक पहुंच है और यह दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचता है। रेडियो लगभग 90 से अधिक वर्षों से भारतीय घरों का हिस्सा बना हुआ है और यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि 1920 के बाद मानव जीवन में रेडियो ने एक क्रांति लाई थी। 13 फरवरी वह तारीख थी जब 1946 में अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया था और संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी। मानवता की सभी विविधताओं का जश्न मनाने के लिए रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम है और लोकतांत्रिक विमर्श के लिए एक मंच का निर्माण करता है। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी ने जब पहली बार इटली में 1895 में रेडियो सिग्नल भेजा और उसे सुना तो भविष्य का इतिहास वहीं अंकित हो गया था। इसके बाद निरंतर तरक्की होती रही। ऐसे में रेडियों के बारे में बात करना और आकाशवाणी में काम करना अपने आप में गर्व की बात है। रेडियो यानी आवाज की वो दुनिया, जिसमें बाते हैं, कहानियां, गीत-संगीत, नाटक, रूपक और बाल कार्यक्रम हैं। महिलाओं का कार्यक्रम, बुजुर्गों और युवाओं का कार्यक्रम है। अब रेडियों के कार्यक्रम दूरदूर्शन ,यूट्यूब और कई सोशल मीडिया प्लैटफार्म पर आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं। आज आकाशवाणी की अपनी वेबसाइट है ,यूट्यूब चैनल है जिसमें हर कार्यक्रम,हर खबर मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आवाज की ये दुनिया आगे भी ऐसे ही चलती रहे क्योंकि आज भी दूरदराज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो रेडियो ही सुनना पसंद करते हैं।

डिजिटलीकरण के इस दौर में इंटरनेट संचार एवं सूचना प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। इस क्रम में ऐसा प्रतीत होने लगा था कि रेडियो की आवाज दबकर रह जाएगी। लेकिन रेडियो अपनी अंतर्निहित विशिष्टताओं के कारण निरंतर जन-जन तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने के क्रम में एक प्रासंगिक माध्यम के रूप में हमारे समक्ष मौजूद रहा। शहरों में निश्चित रूप से लोग टेलीविजन तथा अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ओर आकर्षित हुए, लेकिन कस्बों व गांवों में अभी भी रेडियो सुना जाता है। जहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, यातायात के साधन नहीं हैं वहां भी रेडियो उपस्थित है, सस्ता, सुलभ और सुविधाजनक।

जिनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है वे अखबार नहीं पढ़ सकते लेकिन रेडियो सुन सकते हैं। जो लोग अपनी दृष्टिहीनता के कारण न तो अखबार पढ़ सकते हैं न टेलीविजन देख सकते हैं, रेडियो उनका भी साथी है और पथप्रदर्शक भी। तीसरी दुनिया के देशों में रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जिसे वास्तव में जनमाध्यम कहा जा सकता है।

रेडियो श्रोताओं को साथ लेकर चलता है और वह उनकी बुद्धि, सोच, और कल्पनाशक्ति पर भरोसा करता है और उन्हें विस्तार तथा सोचने की खुराक भी देता है। कई बार हम सभी के मन के ताने-बाने के अनुरूप हमारे मिजाज में एक ऐसा एकाकीपन जरूर आता है, जब हम गजलों की मखमली आवाज को सुनकर उसे गुनगुना कर उस वक्त को बिताना चाहते हैं, ऐसे में रेडियो हमारा साथ निभाता है। चाहे किचन में काम करती हुई महिलाएं, रातों में पहरा देते चौकीदार, सीमा पर देश की रखवाली करते हुए जवान या दफ्तर से घर आने-जाने के दौरान ट्रैफिक में फंसे लोगों का रेडियो एक हमजोली की तरह साथ निभाता है।

भारत के संदर्भ में बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक एवं बहुस्तरीय जनता की अपनी विशिष्ट आवश्यकता है। यहां स्थानीय रेडियो केंद्रों में अपार वृद्धि होनें से स्थानीय लोग अपनी भाषा, रुचि, आवश्यकताओं एवं समय के अनुरूप कार्यक्रम में भागीदार होते हैं। रेडियो अपनी इसी विशिष्टता के कारण जन-साधारण तक पहुंचने में सफल रहा है। और यह तत्व भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को सुदृढ़ता प्रदान करता है। रेडियो द्वारा श्रोताओं को अपने कार्यस्थल से लेकर विश्व के किसी भी हिस्से में घट रही घटनाओं और हो रहे परिवर्तनों की जानकारी रखने का त्वरित अवसर प्राप्त होता है। रेडियो में परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन की क्षमता होती है। उसे किसी भी स्थान, किसी भी समय तथा श्रोताओं के किसी भी वर्ग की आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाया जा सकता है। रेडियो एक ध्वन्यात्मक माध्यम होते हुए भी सरकारी नीतियों व सेवाओं की जानकारी लक्षित वर्ग तक पहुंचाता है। जैसे- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि तथा स्थानीय सामाजिक समस्याओं, जैसे- दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, जनसंख्या नियंत्रण आदि के विषय में जानकारी प्रदान कर सहभागिता को बढ़ावा देता है साथ ही साथ उन्हें प्रगति के पथ पर चलने हेतु आह्वान भी करता है। सरकार की लोन सुविधा मुद्रा योजना, सिडबी बैंक, नाबार्ड, स्टार्ट-अप-इंडिया आदि जैसे कार्यक्रमों की जानकारी का विश्लेषणात्मक आयाम प्रस्तुत कर अर्थव्यवस्था में सामुदायिक हिस्सेदारी को बढ़ाता है। रेडियो दृश्यहीन माध्यम होने के कारण ही लोगों की कल्पना शक्ति को संपन्न करता है। यह अपने ध्वनि प्रभाव के माध्यम से मानव की मानसिक क्षमता को जागरूक कर दृश्यों के निर्माण को संभव करता है। इसीलिए रेडियो को कल्पनाशक्ति कौशल की संज्ञा दी गई है। रेडियो कार्यक्रम अपने लक्ष्य समूहों में जीवन संबंधी महत्वपूर्ण बातों जैसे- रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय तथा अनेक ज्ञानवर्धक सूचनाओं को शामिल करता है। रेडियो में मात्र ध्वनि के कारण इसका कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण सरल होता है। इस कारण यह एक काम खर्चीला मध्यम है।

जहां चाह वहां राह..! पढ़ें एक परिवार के प्रयागराज पहुंचने की रोमांचक कहानी

कहावत है ना कि जहां की चाह हो वहां का रास्ता येन-केन-प्रकारेण निकल ही जाता है। ऐसे में बात यदि आस्था-विश्वास की हो और भीतर का अंतर्मन किसी आस में एक तीर्थ की ओर जाने के लालायित हो तो फिर सब संभव भी हो जाता है। प्रयागराज रील्स, भगदड़ और किलोमीटर तक फैले जाम के बीच एक नौकरीपेशा मन में वहां जाने की कल्पना उठना ही बड़ी बात है। हमारे मन में भी कुछ ऐसा ही था। महाकुंभ में जाने का रत्ती भर भी ख्याल नहीं आया था। मान लीजिए ख्याल आ भी जाए तो जिस तरह के हालात वहां हैं व्यक्ति फौरन उस ख्याल को साइड लगा देगा। लेकिन क्या कहें हमारे भाग्य में वह यात्रा थी तो फिर वह योग घट ही गया।

दरअसल योग ऐसा बना कि विपरीत हालात में डुबकी लगा ही ली, वो भी जब तब सड़कों पर महाजाम था। रेलवे स्टेशनों पर तिल रखने जितनी जगह नहीं थी। एक दिन सुबह अचानक प्रिया (स्कूल के दिनों की दोस्त) का कॉल आया। कुंभ चलना है क्या ? पहले तो मैंने इनकार कर दिया क्योंकि भीड़ में जाना मुश्किल सा लग रहा था। प्रिया का कॉल कट होने के बाद पत्नी अर्पणा ने पूछा तो मैंने बात बताई। उसने बोला कि जब टिकट हो रहे है तो प्लान करो। 8 फरवरी के टिकट हो गए। प्रिया और उसके पति रविंदर घर आए तो खबरें आने लगी कि प्रयागराज में भीड़ बढ़ने लगी है। फिर भी हम सुबह कार से निकल गए। भोपाल से दो साथी महिमा और विजय का साथ मिल गया। भोपाल में कार रखी और ट्रेन में सवार हो गए।रीवा तक पहुंचते उससे पहले ही टैक्सी वाले ने फोन पे पर एडवांस रिटर्न कर दिया। यह बोलकर कि रीवा

हाईवे जाम है। गाड़ी से नहीं जा सकते, आप वापस इंदौर लौट जाए। सभी ने सोच रखा था कि जाएंगे तो जरूर। आखिर इंदौरी पीछे हटने वालों में से नहीं है। टिकिट रीवा तक था, लेकिन हम सतना में ही उतर गए, क्योंकि वहां से ट्रेनें ज्यादा थी। वन्दे भारत से रात साढ़े 11 बजे स्टेशन पर उतरे तो प्लेटफार्म पर बैठने की जगह नहीं मिली। तीन घंटे खड़े रहे। ट्रेन आ जा रही थी, लेकिन लोगों ने भीतर से गेट बंद कर रखे थे। तीन ट्रेनें गुजर गई,एक भी दरवाजा खुला नहीं मिला। लगा कि अब प्रयागराज नहीं जा पाएंगे। जिस प्लेटफार्म पर खड़े थे, वहां उल्टी दिशा से एक ट्रेन आकर खड़ी हो गई। खाली ट्रेन देख कर अर्पणा ने बोला कि काश इसका इंजन मुड़ जाए और ये ट्रेन प्रयागराज ले चले। पांच मिनट के बाद उसका सोचा सच हो गया।

उसी ट्रेन को लेकर अनाउंसमेंट हुआ -

जो यात्रीगण प्रयागराज जाना चाहते है% वे प्लेटफार्म नंबर तीन की ट्रेन में सवार हो जाए। वो ट्रेन हमारे सामने ही खड़ी थी। उसका दरवाजा खुला और हम ट्रेन के भीतर, लेकिन संघर्ष बाकी था। वो ट्रेन प्रयागराज नहीं गई। उसने सभी को प्रयागराज से 100 किलोमीटर पहले उतार दिया। हम फिर भीड़ भरे मानिकपुर स्टेशन पर थे। दो ट्रेन आई और गुजर गई। लोग दरवाजे पर लटक कर सफर कर रहे थे। टॉयलेट के कैबिन तक में लोग बैठे थे। एक ट्रेन रुकी। गलती से एक डिब्बे का दरवाजा खुला। बस फिर क्या था। हमने ट्रेन में जगह बना ली। धक्के मार-मारकर गेट पर छह लोगों के लिए जगह बना दी। ट्रेन चल पड़ी। तीन घंटे खड़े -खड़े सफर, फिर आ गई मंजिल। प्रयागराज की धूल ने हमारा स्वागत किया।

20 किलोमीटर पैदल चले, आस्था की डुबकी लगाई और उसी रात फिर भीड़ से भरी ट्रेनें में सवार हो गए। तीन घंटे खड़े खड़े ट्रेन के सफर के बाद सतना स्टेशन आया। रात एक बजे स्टेशन पर खाना खाया। स्टेशन पर ही रात गुजारी और सुबह छह बजे वहां से वंदे भारत ट्रेन भोपाल के लिए पकड़ी। दोपहर दो बजे भोपाल उतरे। फिर भोपाल में घूमे और इंदौर आए।

तीन रात जागने के बाद घर पर फिर उसी बिस्तर पर कमर सीधी हुई जिससे उठ कर हम तीन दिन पहले प्रयागराज के लिए निकले थे। फिर भी ये ट्रीप यादगार रही क्योंकि उत्साह था, दोस्तों का साथ था और जिद थी, जो पूरी हुई। त्रिवेणी संगम की गोद में आस्था की सुकून

अबुझमाड़ मैराथन 2025-वॉल पेटिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन

विजेताओं को मिलेंगें आर्कषक ईनाम

नारायणपुर, जिला एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में देश-विदेश में अबुझमाड़ की अद्वितीय प्राकृति सौन्दर्य को उजागर करने एवं खेलों के प्रति युवाओं को प्रेरित करने के आशय से नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ हॉफ मैराथन का आयोजन 02 मार्च 2025 को बालक हाई स्कूल ग्राउण्ड से किया जा रहा है इसी कड़ी में दिनांक 16.02.2025 को सुबह 07:00 बजे हाई स्कूल ग्राउण्ड नारायणपुर में अबुझमाड़ मैराथन 2025-वॉल पेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया हैं।

प्रतियोगिता में अबुझमाड़ की संस्कृति, लोककला एवं प्रकृति को उकेरने का अवसर है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को आयोजक समिति की ओर से रंग उपलब्ध कराया जायेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का एक सुनहरा अवसर है इस अवसर को ना खोयें और अधिक से अधिक संख्या में वॉल पेटिंग प्रतियोगिता में भाग लेवें। विजेताओं को विशेष आर्कषक ईनाम दिया जायेगा।

एसपी नारायणपुर श्री प्रभात कुमार (भा.पु.से.) एवं एडिशन एसपी श्री रोबिनसन गुड़िया (भा.पु.से.) ने अपने विचार व्यक्त किये कि पेंटिग एक कलात्मक माध्यम है जिसमें विभिन्न रंगो एवं तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न भावनाओं, विचारों और दृश्यों को उजागर किया जाता है। पेंटिग में कलाकार अपनी भावनाओं को रंगो और अकारों के माध्यम से व्यक्त कर सकता है विचारों और अवधारणों को दृश्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। पेंटिग में विभिन्न दृश्यों को चित्रित जैसे की प्राकृतिक दृश्य, शहरी दृश्य या कल्पनात्मक दृश्य, संस्कृति या परम्पराओं को प्रदर्शित कर सकता है। पेंटिग में कलाकार अपनी आत्मा और व्यक्तित्व को व्यक्त कर सकता है। अपील किया जाता है कि उक्त प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभागी भाग लेकर वॉल पेंटिग प्रतियोगिता को सफल बनाकर आकर्षक ईनाम पाएं।

मानव कल्याण मंच की ओर से श्री जैन कन्या हाई स्कूल देवबंद में 41 जरूरतमंद स्कूली बच्चों को जूते व जुराब वितरित किए गए

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर । देवबंद, मानव सेवा को समर्पित संस्था मानव कल्याण मंच देवबंद द्वारा नर सेवा नारायण सेवा के सूत्र को अपनाकर किये जा रहे सेवा कार्यों की कड़ी में आज श्री जैन कन्या हाई स्कूल देवबंद में 41 जरूरतमंद स्कूली बच्चों को जूते व जुराब वितरित किए गए। आज के कार्यक्रम में मानव कल्याण मंच महिला मंडल की कोषाध्यक्ष श्रीमती ममता वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि जरूरतमंद बच्चों की सेवा करना परम पुण्य कार्य है क्योंकि ये छात्राएं पढ़कर आगे भविष्य में डाक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यवसायी बनेगी। मंच लगातार 29 वर्षों से सेवा कार्य कर रहा है तथा समाज के प्रत्येक वर्ग की सहायता भी अपने सदस्यों के सहयोग से कर रहा है।

मानव कल्याण मंच के संस्थापक अरुण अग्रवाल ने कहा कि अपने लिए तो सभी इंसान जीते हैं लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसे ही असल जिंदगी कहते हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद करना तथा हर पल उनके साथ खड़े रहना इसी का नाम जिंदगी है। जब कोई संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाती है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता और गरीबों की दुआओं में जो असर होता है उसका कोई मोल नहीं होता। यह दुआएं कभी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती द्य जरूरतमंदों की मदद निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए क्योंकि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल हमेशा मीठा होता है, और यही पुनीत कार्य है। हमसे जो कुछ भी बन पाता है हम निस्वार्थ भाव से निर्धन व असहाय लोगों की सेवा करते हैं। मंच के अध्यक्ष सुशील कर्णवाल ने बताया कि मंच 1995 से लगातार निर्धनों व सामाजिक रूप से पिछड़े असहाय लोगों मदद कर रहा है। सेवा करने से आत्म संतुष्टि की अनुभूति होती है। हमारा उद्देश्य समाज के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक अपनी सेवा पहुंचाना है। स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती वंदना जैन ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे जरूरतमंद बच्चों की मदद करना ही वास्तव में सच्ची सामाजिक व नर नारायण सेवा है। उन्होंने बताया कि मंच हमारे स्कूल के बच्चों की सेवा पिछले कई वर्षों से लगातार सेवा कर रहा है इसके लिए वह मानव कल्याण मंच का हृदय से आभार व्यक्त करती हैं।

मानव कल्याण मंच महिला मंडल की वरिष्ठ सदस्या श्री मति अंजलि त्यागी ने मंच द्वारा किए जा रहे मासिक सेवा कार्यो की सराहना की। महासचिव राजू सैनी ने मंच द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में विस्तार से बताया तथा स्कूल प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुरमीत बेदी, पूनम भटनागर, जूही जैन, शुभलेश शर्मा, राजीव शर्मा, बाबू चन्द्रप्रकाश गाबा,सुनील बंसल,अमन गोयल आदि उपस्थित रहे।

बिजली चोरी करने पर लगेगा जुर्माना होगी जेल - जिलाधिकारी मनीष बंसल

चैकिंग अभियान में पकड़ी गयी 109 लाख की विद्युत चोरी

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशानुसार विद्युत विभाग द्वारा पीएसी बल के साथ जनपद में विद्युत चोरी के प्रकरणों को रोकने के लिए चैकिंग अभियान चलाया गया। चोरी के प्रकरणों को रोकने से न केवल पोषक पर भार घटेगा अपितु सरकार के राजस्व में भी बढोत्तरी होगी। डीएम मनीष बंसल ने कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 (बी) बिजली की लाइन के साथ मीटर को अनधिकृत रूप से फिर से जोड़ने के अपराध से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति बिजली की आपूर्ति कट जाने के बाद अवैध रूप से फिर से जोड़ता है, तो उसे तीन साल तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अनधिकृत रूप से फिर से कनेक्शन के माध्यम से बिजली चोरी को अनिवार्य रूप से अपराध माना जाता है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 बिजली चोरी के अपराध से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि बिजली चोरी करने पर कारावास, जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। 15 जनवरी से 11 फरवरी तक विभिन्न खण्डों में चलाए गये चैकिंग अभियान के दौरान 3201 रेड डाली गयी जिसमें 801 विद्युत चोरी के प्रकरण पकडे गये। इन विद्युत चोरी के 381 प्रकरणों में 135 एवं 420 प्रकरणों में 138बी के अनुसार एफआईआर दर्ज करा दी गयी है। इस दौरान जनपद के 1466 बडे बकायादारों को विच्छेदित किया गया जिन पर कुल 761.10 लाख की धनराशि बकाया है। चैकिंग से पूर्व पोषक पर 1318 एम्पीयर का भार था जो अब घटकर 1090 एम्पीयर रह गया है। चैकिंग अभियान में 109 लाख की विद्युत चोरी पकड़ी गयी। चैकिंग अभियान के दौरान 15 जनवरी को विद्युत नगरीय वितरण खण्ड जनकनगर के 11 केवी पोषक किशनपुरा, पुलखुमरान एवं हुसैनबस्ती में चैकिंग अभियान चलाया गया। 16 जनवरी को विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम के ढोली खाल एवं दाउद सराय में, 17 जनवरी को वि0वि0ख0 नकुड़ के गंगोह प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में, 18 जनवरी को वि0वि0ख0 द्वितीय के मनानी में, 20 जनवरी को वि0वि0ख0 सरसावा के नवादा एवं रायपुर में, 21 जनवरी को वि0वि0ख0 सरसावा के पंचकुआ, लालवाला, पठेड में, 22 जनवरी को वि0वि0ख0 बेहट के कमेशपुर, छुटमलपुर में, 23 जनवरी को वि0वि0ख0 द्वितीय के फिरहेडी, 24 जनवरी को वि0वि0ख0 नकुड़ के सरसावा रोड़, 25 जनवरी को वि0वि0ख0 नकुड़ के खारीबांस, 27 जनवरी को वि0वि0ख0 देवबन्द के नागल, 28 जनवरी को वि0वि0ख0 देवबन्द के नन्हेडा एवं बुड्ढाखेडा, 29 जनवरी को वि0वि0ख0 सरसावा के संकरपुर एवं हसनपुर, 30 जनवरी को वि0न0वि0ख0 प्रथम के गोटेशाह बरेलियों का मदरसा, 31 जनवरी को वि0न0वि0ख0 जनकनगर के जैनबाग, वर्धमान, धोबीघाट एवं निसार रोड पर चैकिंग अभियान चलाया गया। इसी प्रकार 01 फरवरी को विद्युत वितरण खण्ड बलियाखेडी के घाटेडा, 03 फरवरी को वि0वि0ख0 बलियाखेडी के लण्ढौरा, 04 फरवरी को वि0वि0ख0 बलियाखेडी के बडेडी, 05 फरवरी को वि0वि0ख0 बेहट के गणेशपुर, 06 फरवरी को वि0वि0ख0 बेहट के खुजनावर, 07 फरवरी को वि0वि0ख0 देवबन्द के खेडामुगल, 10 फरवरी को वि0न0वि0ख0 प्रथम के मेहंदी सराय, गढी चुंगी, 11 फरवरी को वि0न0वि0ख0 द्वितीय के किशनपुरा, पुलखुमरान एवं हुसैनबस्ती में चैकिंग अभियान चलाया गया।

मण्डलायुक्त के निर्देशों पर कार्य करने में संयुक्त आयुक्त उद्योग को मिला सम्मान

सूक्ष्म एवं लघु फैसिलीटेशन काउन्सिल सहारनपुर को लघु उद्यमों के लम्बित भुगतान संबंधी विवादों के निस्तारण में किये गये उत्कृष्ट कार्य हेतु किया गया सम्मानित

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर, सूक्ष्म एवं लघु फैसिलीटेशन काउन्सिल सहारनपुर को चैम्बर ऑफ इण्डियन माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इण्टरप्राइजेज नई दिल्ली द्वारा लघु उद्यमों के लम्बित भुगतान संबंधी विवादों के निस्तारण में किये गये उत्कृष्ट कार्य करने हेतु एमएसएमई बैंकिंग एण्ड एमएसईएफसी एक्सीलेन्स अवार्ड-2024 का कार्यक्रम आयोजित दि-इम्पीरियल होटल, जनपत, न्यू दिल्ली में पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार, दीपक वर्मा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, मुकेश मोहन गुप्ता, प्रेसिडेन्ट, चैम्बर ऑफ इण्डियन माइक्रो स्मॉल एण्ड मिडियम इण्टरप्राईजेज, न्यू दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है।संयुक्त आयुक्त उद्योग श्रीमती अंजू रानी ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डवलपमेन्ट एक्ट-2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लम्बित भुगतान संबंधी विवादों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित मण्डलीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलीटेशन काउन्सिल सहारनपुर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित की गयी है, जिसमें संयुक्त आयुक्त उद्योग, सहारनपुर मण्डल, सहानपुर, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक, अनुपम गुप्ता प्रतिनिधि- लघु उद्योग भारती तथा प्रमोद मिगलानी प्रतिनिधि- आईआईए सदस्य है। उल्लेखनीय है कि फैसिलीटेशन काउन्सिल सहारनपुर द्वारा मध्यस्था के माध्यम से 82 इकाईयों की लगभग रू0 3,29,84,778.00(रू0 तीन करोड उन्नतीस लाख चौरासी हजार सात सौ अठ्हत्तर मात्र) की धनराशि का भुगतान कराया जा चुका है तथा आब्रीटेशन के माध्यम से 153 इकाईयों के लगभग रू0 14,93,02,001.00 (रू0 चौदह करोड तिरानवे लाख दो हजार एक मात्र) की धनराशि के आवार्ड(आदेश) निर्णित किये गये है। इसके अतिरिक्त मण्डलीय फैसिलीटेशन काउन्सिल सहारनपुर द्वारा सम्बन्धित जिला कलेक्टर को 61 वसूली प्रमाण पत्र भुगतान कराये जाने हेतु निर्गत किये गये थे, जिसके फलस्वरूप 02 इकाईयों के रू0 3,30,544.00 (रू0 तीन लाख तीस हजार पांच सौ चवालीस मात्र) की रिकवरी जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसका भुगतान सम्बन्धित इकाई को कर दिया गया है।

गुरू रविदास जी के 648 वें जन्मोत्सव पर आयोजित शोभायात्रा में शामिल सभी सदस्यों को पगडी

पटका पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर । देवबंद, संत शिरोमणि गुरू रविदास युवा समाज विकास समिति द्वारा आयोजित गुरू रविदास जी के 648 वें जन्मोत्सव पर नगर में आयोजित शोभायात्रा में शामिल सभी सदस्यों को पगडी, पटका पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।

समारोह में कार्यक्रम के संयोजक राजकुमार जाटव ने गुरू रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माघी पूर्णिमा को काशी में एक साधारण परिवार में जन्मे संत रविदास ने अपने असाधारण चिंतन कर्म योगी के द्वारा आध्यात्मिक जगत में प्रतिष्ठा पाई। उन्होंने लोगो को बताया कि व्यक्ति का धर्म कोई भी लेकिन कर्म ही उसे महान बनाता है। समिति के अध्यक्ष बाबूराम ने भी विचार व्यक्त किये। कहा कि हमको संतो के बताये मार्ग पर चलकर समाज में बुराइयों का अन्त करके सच्चाई के मार्ग चलना है।इस अवसर पर महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष उमेश कुमार, आडिटर नितिन कुमार, वेद प्रकाश जाटव, यशपाल सिंह, डा0 सत्यम, विक्की, निगम, अरविंद कुमार, अमरदीप, दलीप कुमार, पंकज कुमार, सन्नी कुमार, शुभम निगम, प्रवीण कुमार, सुशील जाटव, राजकुमार जाटव, मोहित जाटव, संदीप कुमार जाटव आदि उपस्थित रहे।

पंचकल्याणक महोत्सव में पहुंचे मंत्री प्रहलाद पटेल, मुनि श्री से लिया आशीर्वाद

सनातन धर्म ही विश्व को दिशा देने में सक्षम- प्रहलाद पटेल

सुनील यादव । सिटी चीफ

कटनी, कटनी में जैन समाज द्वारा आयोजित पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव में शामिल होने केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का कटनी आगमन हुआ। उन्होंने झुरही स्थित चेतनोदय तीर्थ स्थल पहुंचकर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को श्रीफल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वही पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि इस भव्य आयोजन में शामिल होकर मुनि श्रीं का आशीर्वाद का अवसर मिला इसके लिए स्वय का धन्य मानता हूं। उन्होंने कहा आप सभी सौभाग्यशाली है जो इस पावनतीर्थ में हो रहे समागम के साक्षी बने। वही भारत देश में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने और दुनिया को दिशा देने के लिए कोई और दूसरा रस्ता नहीं है।

कटनी पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में एमपी सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि लोग हिंसा और ताकत के बल पर अपना विस्तार करना चाह रहे भारत की धरती में पैदा हुआ कोई धर्म ऐसा नहीं है जो शस्त्र लेकर समर्थ की दम पर कभी अधिपत्य स्थापित करना चाहा हो वह सदैव सत्य और अहिंसा की मार्ग पर चलने की राह देता है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले कोई लीडर है तो हम है, यदि दुनिया में शांति स्थापित होनी है तो यही विचार यही धर्म यही पूजा यही पद्धतियां यही दुनिया को शांति दे सकती है। वही प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के बारे में विपक्ष द्वारा की जा रही टिप्पणियों के बारे में कहा कि जो लोग नहा के आ रहे है उनसे पूछिए वहां जाने का कष्ट बढ़ा रहता है 12-12 घंटे लबे जाम में फंसे रहते है, लेकिन गंगा में डुबकी लगाकर लौटते है और जब उनसे पूछा जाता है तो वह उस प्रतिक्रिया के साथ है, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया के साथ नहीं है जो चोरी छुपके डुबकी मार देते है उनपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।

कटनी में सहकारी समिति कर्मचारियों का विरोध

लंबित भुगतान जल्द करने की मांग

कटनी, कटनी के प्राथमिक सहकारी समिति कर्मचारी संघ भोपाल के कर्मचारियों ने समर्थन मूल्य धान खरीदी से संबंधी लंबित भुगतान अविलंब किये जाने पर जोरदार नारेबाजी कर कटनी कलेक्टर और सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन जिला कटनी के अधिकारी को सौपा।

प्राथमिक सहकारी समिति कर्मचारी संघ भोपाल के कर्मचारियों ने बताया कि कटनी जिले के अंतर्गत समर्थन मूल्य धान खरीदी से संबंधित लंबित भुगतान के संबंध में जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम से लगातार संपर्क भुगतान हेतु किया जा रहा है परंतु आज दिनांक तक धान खरीदी वर्ष 2021-22 के दौरान 7.30 करोड़ की राशि ऑनलाईन एवं ऑफलाईन के विवाद में नान द्वारा कर एक ही राशि को ऑनलाईन एवं उसी राशि को ऑफलाईन बताया जाकर भुगतान रोका गया है। धान खरीदी वर्ष 2022-23 की लोडिंग राशि का भुगतान आज दिनांक तक नही किया गया। धान खरीदी वर्ष 2023-24 के हेण्डलिंग एवं लोडिंग दोनो का भुगतान नही किया गया। जिससे खरीदी प्रभारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वर्ष 2023-24 के संस्था कमीशन 31.25 हज़ार रूपये में से कुल 17 रूपये के हिसाब का भुगतान किया गया है। शेष 14 लाख 25 रूपये भुगतान समितियों को होना शेष है। जो राशि पूरे जिले की लंब संब 5 से 8 करोड़ के बीच होती है। वर्तमान वर्ष 2024-25 के दौरान खरीदी समाप्त हो चुकी है उसकी भी लोडिंग एवं हेण्डलिंग का भुगतान खरीदी प्रभारियों को लंबित है। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। समितियां से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की 54 समितियां का भुगतान किया जाना शेष है वही वही इस समितियां के कार्य में लगे 80 कंप्यूटर ऑपरेटर का भुगतान भी लंबित है। यही सभी के भुगतान के लिए आज सभी खरीदी प्रभारियों ने जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।

अखिल भारतीय सफाई मजदूर काग्रेस ट्रेड यूनियन के वैनर तले 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन

सुनील यादव । सिटी चीफ

कटनी, अखिल भारतीय सफाई मजदूर काग्रेस ट्रेड यूनियन के सदस्यों के नेतृत्व में कुछ सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर नारेवाजी करतें हुए एक ज्ञापन पत्र नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे को सौंपा, जिसमे उल्लेख किया गया कि संघ के द्वारा आपसे आग्रह किया जाता हैं कि नगर पालिक निगम में 15-20 वर्षों से लगातार फिक्स एवं दैनिक सेवा दे रहे सफाई कर्मचारी अपने हक एवं अधिकार के लिए निवेदन करते हैं, वे अपनी जान जोखिम में डालकर रात-दिन मेहनत कर शहर को स्वच्छ बनाने में लगे रहते हैं। साथ ही कोरोना जैसी महामारी में भी कर्तव्य के प्रति तत्परता दिखाया है. किन्तु उन्हीं की जायज मांगों को नजर अंदाज कर उनके हक एवं अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर काग्रेस ट्रेड यूनियन की 05 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से विनियमित सफाई मित्रों को अविलंब नियमित किया जावे। शासन के आदेशानुसार 2007 से 2016 तक के समस्त फिक्स एवं दैनिक वेतनभोगी सफाई मित्रों को वरिष्ठता के आधार पर अविलंब विनियमित किया जावे। 33 दैनिक वेतनभोगी सफाई मित्रों को फिक्स वेतन का लाभ अविलंब दिया जावे। फिक्स एवं दैनिक सफाई मित्रों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन अविलंब किया जावे। वरिष्ठता सूची के अनुसार और कार्य को दृष्टिगत रखते हुए विशेष भत्ता कुशल श्रमिक का लाभ अविलंब प्रदाय किया जावे इन सभी मांगों को लेकर ज्ञापन नगर निगम आयुक्त को सौंप अविलंब निराकरण किए जाने की मांग की गईं हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में एकदिवसीय मीडिया कार्यशाला आयोजित

लकेश पंचेश्वर। सिटी चीफ

लालबर्रा, नगर मुख्यालय के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 13 फरवरी 2025 को एकदिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें डां.रित्विक पटेल खंड चिकित्सा अधिकारी लालबर्रा,सेवानिवृत्त डॉ टी सी मेश्राम,भुनेश्वर बोपचे बीपीएम, संतोष दुधमोगरें ब्लांक एकाउंट मैनेजर,जे के पंचेश्वर एन एम ए , देवीसिंह ठाकरे प्रभारी बी ई उपस्थित रहे। वहीं एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्रमानुसार मौखिक जानकारी से उपस्थित मीडिया कर्मियों को अवगत करवाया गया जिसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे दस्तक अभियान अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि दस्तक अभियान प्रतिवर्ष दो चरणों में आयोजित किया जाता है जिसमें 0-5 वर्ष आयु के समस्त बच्चों की स्वास्थ्य जांच परीक्षण एवं उपचार प्रदान किया जाता है दस्तक अभियान का प्रथम चरण माह जुलाई अगस्त 2024 में आयोजित किया गया था जिसमें स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से दल एएनएम,सीएचओ,आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा घर-घर जाकर 0-5 वर्ष के समस्त बच्चों को विटामिन ए,अनुपुरण,खुन कि जांच एनीमिया,डायरिया, निमोनिया, नियंत्रण कुपोषण कि पहचान व हत्रष्ट में बच्चों को रेफर और सेवाएं दि जाती है। वहीं दस्तक अभियान का द्वितीय चरण 14 फरवरी से 14 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाना है जिसमें मंगलवार एवं शुक्रवार को ग्रामों में आंगनवाड़ी केंद्रों में होने वाले टीकाकरण दिवस पर एक माह से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को विटामिन ए की खुराक उम्र अनुसार प्रदान की जाएगी साथ ही प्रथम चरण में एनीमिक मिले बच्चों का फॉलोअप एचबी परीक्षण कर आवश्यक उपचार किया जाएगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम - स्थाई साधन नसबंदी (महिला पुरुष)अस्थाई साधन (माला-ह, कंडोम, कापर-टी,अंतरा व छाया) अंत में हास्पीटल उन्नयन के बारे में भी अवगत कराया गया। वहीं उपस्थित मीडिया कर्मियों में प्रमुख रूप से मुकेश अवधिया, राजु पंचेश्वर,श्री विजय रजक जी(वरिष्ठ पत्रकार),सलमान कुरैशी,आशिष भगत,राहुल जैसवाल,लकेश पंचेश्वर,मतीन रज़ा,विजय किरण सोनी,इमरान कुरैशी,प्रकाश चौहान,राजामशीकर व शरद धानेश्वर सहित अन्य सभी पत्रकार साथी उपस्थित रहे हैं।

महाकुंभ न केवल एक त्यौहार है,बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति स्थान है -आनंद

लकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ

लालबर्रा, जनपद पंचायत अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कजंई के सरपंच अधि.आनंद बिसेन सपरिवार प्रयागराज महाकुंभ 10 फरवरी को पहुचे तथा माघपूर्णिमा के पावन पुनीत स्वर्णिम दिन में प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी त्रिवेणी संगम व अरेल घट त्रिवेणी संगम घाट पर में शाही स्नान कर आस्था श्रद्धा भक्ति कि डुबकी लगाकर अखाड़ों और अघोरी बाबा साधु-संतों के दर्शन किए साथ ही साथ श्री सोमेश्वर महादेव,श्री त्रिवेणी संगम मंदिर के दर्शन किए। दुरभाष में जानकारी देते हुए श्री बिसेन ने बताया कि 144 साल बाद महाकुंभ हुआ है तथा प्रयागराज नगरी के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन देश दुनिया के लोगों को आकर्षित कर रहा है महाकुंभ कि शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है जो कि 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा।श्री बिसेन ने आगे बताया कि महाकुंभ धरती पर होने वाला सबसे शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से उर्जा से परिपूर्ण आयोजन है।जो हर 144 साल में एक बार 12 पुर्ण कुंभों के पुरे होने के बाद होता है यह दिव्य आयोजन चार पवित्र स्थानों प्रयागराज,हरिद्वार, नासिक व उज्जैन में सम्पन्न होता है महाकुंभ ना केवल एक त्यौहार है बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति का स्थान है जहां पृथ्वी और ब्राम्हांड कि शक्तियां एक साथ आती है यह आत्म परिवर्तन शुध्दिकरण और कर्मों के चक्र से मुक्ति पाने का एक अनमोल अवसर प्रदान करता है महाकुंभ के आयोजन का समय खगोलीय गणनाओं पर निर्भर होता है जिसमें बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा कि विशेष स्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन ग्रहों कि खास अवस्थाएं एक ऊर्जावान वातावरण बनाती है जिससे आध्यात्मिक साधनाएं और ईश्वरीय जुड़ाव कई गुना बढ़ जाते हैं कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन ग्रहों की ऊर्जा गंगा यमुना और रहस्यमयी सरस्वती नदियों में प्रवाहित होकर उन्हें उच्च ऊर्जा से भर देती है ये नदियां अध्यात्म जागरण और कर्मों के शुद्धिकरण का माध्यम बन जाती है।

कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा चोरो से बरामद तीन लाख के सोने चांदी के जेवरात न्यायालय आदेश पर फरियादी को सौंपे

अनूपपुर, दिनांक 11 अगस्त 2024 को दीपक सोनी (उम्र 31 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 13, पुलिस कॉलोनी रोड, बस्ती रोड, अनूपपुर, ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह अपने परिवार के साथ मैहर दर्शन के लिए गया था, घर पर ताला लगा हुआ था। अगले दिन लौटने पर उसने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और सोने-चांदी के जेवरात चोरी हो गए हैं। इस शिकायत पर कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 378/24, धारा 331(4) और 305 ( ) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी के निर्देशन में कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन के नेतृत्व में उपनिरीक्षक प्रवीण साहू, प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह, शेख रशीद, रितेश सिंह, महिला आरक्षक अंकिता सोनी और आरक्षक अब्दुल की टीम ने मामले की जांच करते हुए मुख्य आरोपी सोनू सिंह (उम्र 21 वर्ष), निवासी ग्राम छपराटोला, ग्राम लखनपुर, थाना कोतवाली, अनूपपुर को गिरफ्तार किया गया। चोरी के जेवरात खरीदने में शामिल राजेश सोनी (उम्र 48 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 15, सोनी मोहल्ला, पुरानी बस्ती, अनूपपुर, और उसकी पत्नी सुधा सोनी (उम्र 45 वर्ष) को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 03 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए, जिनमें पायल, पाजेब, करधन, हाथ की मेहंदी, बच्चों के हाथ और पैर के चूड़े, गले की चेन, ब्रेसलेट, बड़ों के कंगन और चूड़े, और सोने के कान के 5 जोड़ी टॉप्स शामिल हैं। दिनांक 11.02.25 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर श्रीमती चेनवती ताराम द्वारा उक्त प्रकरण में कोतवाली पुलिस द्वारा जप्तशुदा सोने चांदी के जेवरात प्रकरण के प्रार्थी दीपक कुमार सोनी को सुपुर्दनामा पर दिये जाने का आदेश जारी करने पर थाना कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा उक्त सोने चांदी के जेवरात प्रकरण के प्रार्थी दीपक कुमार सोनी पिता छविलाल सोनी उम्र 25 साल निवासी वार्ड न. 03 पुरानी बस्ती अनूपपुर को सौंप दिये गये। घर का रात्रि में ताला तोड़कर चोरी किये गये सोने चांदी के जेवरात वापस पाने पर दीपक सोनी द्वारा अनूपपुर पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए सराहना की है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जिले के 82713 किसानों 16.54 करोड़ रुपए हुए हस्तानांतरित

सुशिल सोनी । सिटी चीफ

अनूपपुर, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रदेश के किसानों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक मजबूती का बड़ा आधार बन रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इसी प्रकार कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी 6000 रुपए की राशि पूर्व से प्राप्त हो रहा है। इसी तारतम्य में 10 फरवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 की तृतीय किस्त और कुल 11वीं किस्त का सिंगल क्लिक के माध्यम से भुगतान किया गया। अनूपपुर जिले के 82713 किसानों के आधार लिंक खातों में 2000 रुपए प्रति किसान कुल 16 करोड़ 54 लाख 26 हजार रुपए हस्तानांतरित की गई।

इस योजना से अनूपपुर जिले के हजारों किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य कृषि को लाभ का धंधा बनाने की संकल्पना को साकार करना, कृषि के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करना, किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसी कड़ी में अनूपपुर जिले के ग्राम बरबसपुर के किसान रघुवीर प्रसाद चतुर्वेदी को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000 प्राप्त हुए। जिसे पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि वे इस पैसे से खरीफ की खेती हेतु धान का बीज खरीदेंगे तथा अच्छी खेती कर कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे। किसान श्री रघुवर प्रसाद चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जैसे किसान हितैषी योजना का संचालन करने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा राज्य सरकार का हृदय से आभार माना। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा किसानों को समृद्ध, संपन्न तथा खुशहाल बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जो सराहनीय है। उन्होंने जिला प्रशासन का भी आभार माना।

नौनिहालों का भविष्य खतरे में कई प्राइवेट स्कूलों में नहीं है कोई भी सुविधा फिर भी सालों से मिली हुई है मान्यता

सुशिल सोनी । सिटी चीफ

अनुपपुर, अनुपपुर जिले में प्राइवेट स्कूल की आड़ में शिक्षा का अधिकार के नियम का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है जिले में कई ऐसे स्कूल संचालित है जिनके पास मान्यता से संबंधित शासकीय नियमों में से एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं है फिर भी इनको सालों से मान्यता प्राप्त है और ये सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है इन प्राइवेट स्कूलों के पास न तो कच्छाओं के लिए पर्याप्त कमरे है न बच्चों के लिए प्रसाधन सुविधा न प्ले ग्राउंड न पीने को पानी की व्यवस्था न ही बैठने के लिए टेबल कुर्सी और न ही पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उसके बाद भी ये बराबर स्कूल का संचालन कर रहे है और इन सभी स्कूलों में

एक समानता है कि इन सब स्कूलों में 30 से 40 बच्चे राइट टू एजुकेशन के है जिनके लिए इन्हें शासन से मोटी रकम हर वर्ष मिल जाती है ,इस प्रकार ये प्राइवेट स्कूल और सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी डी पी सी मिल कर इस शासकीय राशि का दुरुपयोग करते नजर आ रहे है

एक स्कूल में तो दो कमरे हैं और उसमें पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं लग रही है एक स्कूल में कमरे तो है पर वो कब गिर जाए ये कोई नहीं जानता एक स्कूल जिसके कमरों में प्रकाश की एक झलक तक नहीं आती ऐसे न जाने कितने प्राइवेट स्कूल हमारे अनुपपुर जिले में संचालित है ।

रतनगढ़ टी.आई.के पास विधायक की चमचागिरी करने के अलावा और कोई नहीं काम, जनता हो रही परेशान - सत्यनारायण पाटीदार

चोरी,लूट,डकैती, महिला अपहरण में एक भी केस नहीं कर पाए ट्रेस, एनडीपीएस केस में ही टीआई की अधिक है।रुचि-

भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने वाले टीआई की नाकामी से रतनगढ़ क्षेत्र के हालात बद से बदतर-

रतनगढ पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने वाले रतनगढ़ क्षेत्र के टीआई की नाकामी के चलते बीते डेढ़ साल के भीतर चोरी, लूट,डकैती,महिला अपहरण के मामले अधिक बढ़ चुके है। जिसको लेकर क्षेत्र के हालात बदतर हो चुके है।निरंतर हो रही घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो चुका है। रतनगढ़ क्षेत्र के टीआई की निष्क्रियता का आलम यह है।कि वे अपने कार्यकाल के डेढ़ साल के भीतर एक भी केस को आज दिन तक ट्रेस करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सके है।और क्षेत्र वासियों को सुरक्षा प्रदान करने में भी नाकाम रहे है।भाजपा के राज में उनका एजेंट बनकर काम करने वाले रतनगढ़ टीआई की नाकामी और उनका निजी स्वार्थ अब जग जाहिर हो चुका है।किस केस में उनकी रुचि है, किसके संरक्षण अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे है। वो सबके सामने आ चुका है।टीआई की कार्य प्रणाली को लेकर शीघ्र ही पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को शिकायत की तैयारी हो चुकी है।उक्त आरोप लगाए है। जावद विधान सभा के पूर्व जनपद अध्यक्ष व मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यनारायण पाटीदार ने आगे कहा कि चोरी, लूट, डकैती,महिला अपहरण जैसे गंभीर मामलो में चुप्पी साधने वाले वाले रतनगढ़ क्षेत्र के टीआई आज तक एक भी केस को ट्रेस नहीं कर पाए। जब की एनडीपीएस केस में टीआई की रुचि देखते ही बनती है। विधायक की चमचागिरी करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला रतनगढ़ क्षेत्र का टीआई पुलिस विभाग पर बदनुमा दाग बन चुका है।उसे आम जनता की समस्या से कोई लेना नहीं है वह भाजपा के जन प्रतिनिधियों के संरक्षण में उनका एजेंट बनकर काम कर रहा है।और जनता को भगवान भरोसे छोड़ रखा है।

श्री पाटीदार ने आगे कहा कि रतनगढ़ क्षेत्र के टीआई की नाकामी से जग जाहिर हो चुकी है। क्षेत्र की सुरक्षा करने वाला ही खुद विधायक के निजी सेवक के रूप में एजेंट बनकर काम कर रहा है।तो क्षेत्र में आम जनता की स्थिति समझी जा सकती है।क्षेत्र में लूट,चोरी,डकैती, निरंतर हों रही है, लड़कियां घूम हो जाती है,इन प्रकरणों को सुलझाने में डेढ़ साल के कार्यकाल में आज दिनांक तक रतनगढ़ क्षेत्र के टीआई की कोई रुचि नहीं रही है। क्षेत्र में लगभग 10 से अधिक चोरी हो चुकी हैं लेकिन आज तक एक भी ट्रेस नहीं हुई है।उन्होंने सिर्फ एनडीपीएस प्रकरण में ही अधिक रुचि दिखाई है। एनडीपीएस केस में ही अधिक ध्यान लगाने का काम किया है।एनडीपीएस के मामलों में टीआई इतनी अधिक रुचि दिखाता है ।कि वो एनडीपीएस प्रकरण को लेकर जोधपुर जाना होता है।तो 2 घंटे में जोधपुर चला जाता है,ऐसे में टीआई की कार्य प्रणाली उनके स्वार्थ को समझा जा सकता है। इनके खिलाफ कई जन विरोधी कार्य सामने आ चुके है।श्री पाटीदार ने आरोप लगाया कि विधायक का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है।उसके बाद भी क्षेत्रीय विधायक के रतनगढ़ क्षेत्र में होने के बाद उसकी कार की फाटक खोलना,उन्हें प्रोटोकॉल देना, विधायक की चमचा गिरी करने में लग जाता है।वह जनता के सेवक के रूप में नहीं भाजपा के एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है।रतनगढ़ क्षेत्र के टीआई के पास जावद क्षेत्र के विधायक की चमचा गिरी करने के अलावा और कोई काम नहीं है।चाहे जनता परेशान होती रहे।लड़कियां घूम जाती है।तो उसको ढूंढने में कोई रुचि नहीं दिखाता है।

जंगल के रास्ते पर बड़वाह शहर में अवैध रूप से ब्राउन शुगर का विक्रय करने वाले 01 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से ब्राउन शुगर वजनी लगभग 20 ग्राम 30 मिलीग्राम जप्त

जप्तशुदा ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 2,00,000/- रुपये

खरगोन पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना के निर्देशन मे थाना बड़वाह पर अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर का विक्रय करने वाले 01 आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 12.02.25 को थाना बड़वाह पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, दो व्यक्ति इन्दौर से अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लाकर जयंती माता रोड़ जंगल के रास्ते से बड़वाह मे विक्रय करने के लिए थोड़ी देर के बाद आने वाले है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को जयंती माता रोड़ जंगल के रास्तो पर संदिग्धों की सर्चिंग कराई गई जिसमे पुलिस टीम को दो व्यक्ति आते दिखाई दिए जो पुलिस टीम को देख कर भागने लगे । पुलिस टीम के द्वारा पीछा कर 01 व्यक्ति को पकड़ा व दूसरा व्यक्ति मौके से जंगल मे भाग गया । पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पकड़े गए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शेख इकबाल पिता शेख याकूब उम्र 28 वर्ष निवासी कसाई मोहल्ला बड़वाह का होना बताया व मौके से भागे व्यक्ति का नाम अकरम है जो शेख इकबाल का रिश्ते मे साला है ।

शेख इकबाल की जमा तलाशी लेने पर पुलिस टीम को उसके पास से एक पारदर्शी पन्नी मे पावडर भरा मिला, जिसे खोलकर चेक करने पर भूरे रंग का पाऊडर जैसा पदार्थ रखा मिला जो मादक पदार्थ ब्राउन शुगर होना पाया गया जिसे पुलिस टीम के द्वारा विधिवत नियमानुसार जप्त किया गया । मादक पदार्थ ब्राउन शुगर का वजन करते करीब 20 ग्राम 30 मिलीग्राम मिल जिसकी किमती लगभग 2,00,000/- रुपये है । उक्त कृत्य पर से पुलिस टीम के द्वारा आरोपी शेख इकबाल को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना अपराध क्रमांक 76/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है । आरोपी शेख इकबाल के विरुद्ध पूर्व मे थाना बड़वाह पर अपराध क्रमांक 50/2020 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि का पंजीबद्ध है। आरोपी शेख इकबाल को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है जहां से उसका पुलिस रिमान्ड प्राप्त कर मौके से भागे व्यक्ति को गिरफ्तार करने एवं ब्राउन शुगर लाने के संबंध मे विस्तृत पूछताछ की जाएगी ।

जप्तशुदा मशरुका 1. ब्राउन शुगर का वजन करीब 20 ग्राम 30 मिलीग्राम कीमती लगभग 2,00,000/- रुपये

उक्त कार्यवाही में एसडीओपी बड़वाह श्रीमति अर्चना रावत के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी बड़वाह निरीक्षक बलरामसिंह राठौर के नेतृत्व मे उनि. अजय कुमार झा, उनि. मोहरसिंह बघेल व अन्य थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।

बिना अनुमति के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही

पीथमपुर यूनियन कार्बाइड कचरा निष्पादन के संबंध मे कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 24 .1.2025 को संपूर्ण धार जिले में कोई भी रैली धरना विरोध प्रदर्शन को बिना अनुमति किए जाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश 163 बीएनएसएस के तहत जारी किया गया था ।उक्त आदेश का पालन ना करते हुए दिनांक 12.2.2025 को महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति लिए शवासन कर विरोध प्रदर्शन किया गया था जो कि श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा जारी उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन होने से थाना सेक्टर 1 पीथमपुर पर विरोध प्रदर्शन करने वालो के खिलाफ अपराध क्रमांक 80/2025 धारा 223 बीएनएस का पंजीकृत किया गया।

ग्राम दतवाडा के पुराने गांव में वन्यजीव तेंदुए के शावक देखें जाने के बाद से लोगों में भय का वातावरण वनविभाग से की मांग

बड़वानी- जिले की ठीकरी जनपद के ग्राम दतवाड़ा के ग्रामीणों में तेंदुए के शावक पुराने गांव के क्षेत्र में देखें जाने से भय का माहौल बना हुआ है,आज गुरूवार सुबह 10 बजे ग्रामीणों ने जिसे लेकर प्रशासन ओर वन विभाग से इस ओर ध्यान देने की मांग उठाई है, स्थानीय महेंद्र सिंह में बताया कि सप्ताह भर से वन्य प्राणी देखे जाने की चर्चा बनी हुई है,पुराने गांव से झाड़ियां अधिक होने से जानवरों घूमते रहते हैं,डूब प्रभावित इलाकों में कृषक परिवार निवासरत हे जिनके मवेशियों के शिकार करने की घटनाएं आए दिन होती रहती है,रहवासियों ने बताया हे कि लकड़बग्घा,तेंदुए पालतू पशुओ का शिकार करते हैं,घटना के बाद वन विभाग द्वारा पंचनामा बना लिया जाता है जिसके बाद अन्य कोई विकल्प वन विभाग को भी नजर नहीं आता, स्थानीय लोगों द्वारा अपने स्तर पर सुरक्षा के तरीके अपनाए जाते है ।विक्रम सिंह ने बताया कि जंगली जानवरों का प्रकोप है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है,क्षेत्र में मगरमच्छ तेंदुए सहित अन्य जानवर घूमते हैं,बिजली नहीं होने के कारण बहुत समस्या हो रही है,तेंदुए के बच्चे भी देखे गए हैं,प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं ।दिलीप सिंह ने बताया कि उनके एक मवेशी को जंगली जानवर ने क्षति पहुंचाई है,क्षेत्र में अक्सर वन्य प्राणी की चहल कदमी देखी गई हैं,इसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई है। इस सबके बीच ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है।

धूमधाम से मनाई संत शिरोमणि रविदास जयंती

रतलाम/ पिपलौदा - संत शिरोमणि रविदास जन्मोत्सव समिति रतलाम एवं रविदास समाज के तत्वाधान में 12 फरवरी को हर्षोल्लास धूमधाम के साथ संत शिरोमणि रविदासजी महाराज की 648 वी जयंती मनाई गईद्य कार्यक्रम के समापन के अवसर पर देवराज सिंह, उद्योगपति लक्ष्मी नारायण सोलंकी, कर्मचारी नेता अंबाराम बोस, हरिराम जाटव, मेघवाल समाज के जिला अध्यक्ष प्रभु सोलंकी, रविदास जयंती आयोजन समिति के अध्यक्ष राकेश झड़गामा, समाजसेवी रतन लाल लिंबोदिया, मालवीय समाज के जिला अध्यक्ष बाबूलाल मालवीय, चंपालाल सोलंकी, मोतीलाल मालवीय सैलाना, रामचंद्र परिहार, विनोद कटारिया समाजसेवी मंचाशीन थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा संत रविदास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वल किया, तथा महा आरती की गई, तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत आयोजन समिति के भरत लिंबोदिया, कैलाश राठौड़, मांगीलाल झड़गामा, अंबाराम कटारिया, हरिओम सोलंकी, शैलेंद्र परमार, सूरज सोलंकी द्वारा किया गया! आयोजन समिति के प्रभु सोलंकी ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 12 फरवरी को रविदासजी महाराज की जयंती महाआरती, शोभायात्रा और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम 11ः00 बजे संत रविदास चौक कारदी नाका स्थित रविदास मन्दिर पर महा आरती भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय , महापौर प्रहलाद पटेल शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पूर्व विधायक पारस सकलेचा, विशाल शर्मा महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुसुम चाहर की उपस्थिति में आयोजित की गई! इस के बाद कलश एव शोभायात्रा रविदास चौक से प्रारंभ होकर सायर चबूतरा घास बाजार चान्दनी चोक डालूँ मोदी बाजार नाहर पुरा होकर कालिका माता मन्दिर प्रांगण पहुंची! तत्पश्चात रविदासजी महाराज के जीवनदर्शन एवं चिंतन पर सभा एवं संगोष्ठि का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मांगीलाल झड़गामा,चंपालाल सोलकी,आनन्दी बाई परमार, राधेश्याम सोलंकी, शंकर लाल सोलंकी, हरिओम सोलंकी, शैलेंद्र परमार, कन्हैया लाल चौरसिया, सूरज सोलंकी आदि उपस्थित थे कार्यक्रम का संचालन भारत लिंबोडिया द्वारा किया गया, आभार प्रदर्शन प्रभु सोलंकी द्वारा किया गया!

अपार आईडी बनाने के कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्राचार्य, प्रधानपाठक एवं जनशिक्षको का वेतन रोका जाएगा

बड़वानी /बडवानी जिले की समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओ में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने का कार्य प्रचलित है। इस संबंध में समस्त प्राचार्य, प्रधानपाठक एवं जनशिक्षको को समय-सीमा में कार्य कराने हेतु पत्रों, बैठको एवं मोबाईल मैसेज के माध्यम से सूचित किया गया। इसके उपरांत भी अपार आइडी बनाने के कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। कलेक्टर जिला बडवानी सुश्री गुंचा सनोबर द्वारा सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, समस्त संकुल प्राचार्य एवं आहरण संवितरण अधिकारी, समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त बीआरसी को निर्देशित किया गया है। जिन शालाओं के विद्यार्थियों की बिना उचित कारण के 75 प्रतिशत से कम अपार आईडी बनाई जाती है तथा जिस जनशिक्षा केन्द्र की शालाओं में आध्ययनरत कुल विद्यार्थियों की बिना उचित कारण के 75 प्रतिशत से कम अपार आईडी बनाई जाती है, तो ऐसे संस्था प्रमुखों एवं जनशिक्षको का उक्त कार्य होने तक माह फरवरी 2025 से वेतन आहरित नहीं किया जाए। समस्त जनशिक्षको एवं संस्था प्रमुखों को भी इस संबंध में सूचित करते हुए उल्लेखित किया गया है कि वे अपने जनशिक्षा केन्द्र/शाला के विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने का कार्य बिना उचित कारण के 75 प्रतिशत से कम होने पर उनका माह फरवरी 2025 से वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। समस्त अशासकीय शालाओं के संस्था प्रमुखों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपनी शाला में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने का कार्य पूर्ण करे। यदि बिना उचित कारण के लक्ष्य से कम विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जाती है तो उनकी संस्था के विरूद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत मान्यता नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। पत्रों, बैठकों एवं मोबाईल मैसेज के माध्यम से समस्त जनशिक्षकों एवं शासकीय/अशासकीय संस्था प्रमुखों को सूचित किया गया है कि अपार आईजी बनाने के कार्य में कोई कठिनाई है तो तत्काल इसके निराकरण हेतु कार्यवाही करे। कठिनाईयों के निराकरण उपरांत शतप्रतिशत विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाना सुनिश्चित करे।

सावन जाधव 9 वर्ष बाल हृदय सर्जरी के बाद सामन्य बच्चों की तरह दौड़ने लगा

बड़वानी संभाग आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर एवं कलेक्टर जिला बड़वानी के कुशल मार्गदर्शन में 09 नवम्बर 2024 को निजी स्कूल राजपुर में नि:शुल्क शिविर का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत मोबाईल हेल्थ टीम के आयुष चिकित्सक डॉ. गोपाल अग्रवाल द्वारा 02 नवम्बर 2024 को प्रायमरी स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें बच्चे को संभावित बाल हृदय बीमारी चिन्हित की गई। उक्त डॉक्टर द्वारा शिविर में लाने की सलाह माता पिता को दी गई। नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर में विशेष जुपीटर अस्पताल के डॉ. रवीरंजन त्रिपाठी, कॉर्डियॉजिस्ट द्वारा ईको-कॉर्डियोग्राफी की गई। जांच पश्चात उपचार हेतु पीडीए डिवाईस क्लोजर सर्जरी होना आवश्यक बताया गया। जिसका नि:शुल्क उपचार आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत 14 फरवरी 2025 को विशेष जुपिटर अस्पताल इन्दौर किया गया है। उक्त परिवार द्वारा द्वारा बताया गया कि उनकी पारिवारिक आर्थिक बहुत ही दयनीय थी, बच्चे का ईलाज कराना संभव नहीं था। बच्चे एवं माता पिता के लिये आयुष्मान भारत योजना वरदान साबित हुई। सर्जरी होने के बाद बच्चे के माता पिता बहुत खुश है। मरीज के माता पिता द्वारा शासन प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम का आभार व्यक्त किया गया।

कलेक्टर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक

झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में आयोजित शान्ति समिति की बैठक में समस्त उपस्थित सदस्यों से सौहार्द्रपूर्ण रूप से त्यौहार मनाये जाने हेतु सुझाव प्राप्त किये गये, साथ ही पिछले वर्षों मे कुछ असुविधा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। शांति समिति को अवगत कराया गया कि आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए 14 फरवरी 2025 को शब-ए-बारात, 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर्व, 01 मार्च 2025 रमजान प्रारंभ, 07 मार्च 2025 से 13 मार्च 2025 तक भगोरिया पर्व, 13 मार्च 2025 को होलीका दहन, 14 मार्च 2025 को धुलेंडी एवं गल-चूल पर्व, 18 मार्च 2025 को रंगपंचमी, 21 मार्च 2025 शीतला सप्तमी, 28 मार्च 2025 को जमात उल विदा, 31 मार्च 2025 को इद-उल-फितर, 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती, 14 अप्रैल 2025 को डॉ. अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल 2025 को गुड फ्राइडे, 30 अप्रैल 2025 को परशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया आदि अन्य त्यौहार मनायें जायेंगे। आगामी त्यौहारों/पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक स?द्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिये असामाजिक तत्वों, अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिला झाबुआ क्षेत्रान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया । कलेक्टर नेहा मीना द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यो को आने वाले त्यौहार की शुभकामनाएं एवं बधाईयां दी। उन्होंने कहा कि झाबुआ अपने सौहार्द्र और शान्ति के लिए जाना जाता है और इसी परम्परा को बरकरार रखना है। साथ ही अनुविभाग स्तर पर भी शांति समिति की बैठक आयोजित करने, भगोरिया के दौरान मेला स्थल की व्यवस्थित मार्किंग एवं रैंकी किये जाने हेतु निर्देशित किया। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से झूलो के प्रमाणीकरण किये जाने एवं मेला स्थल पर पेयजल, अस्थाई चिकित्सालय, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था किये जाने के साथ किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलुस में रास्ते में साफ-सफाई सुनिश्चित किये जाने हेतु कहा। पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल ने कहा कि प्रशासन एवं समाज के बीच समन्वय स्थापित कर सौहार्दतापूर्वक त्यौहार मनाये जाए। उन्होने बताया कि प्रयास किये जाएंगे कि भगोरिया के दौरान प्रकाश के रहते ही मेला स्थल से गंतव्य की ओर प्रस्थान सम्भव हो सके। इसके साथ ही कुछ भगोरिया स्थलो पर ड्रॉन के माध्यम से कवर किया जाएगा। बैठक में शान्ति समिति के सदस्य ओम शर्मा द्वारा हनुमान जयन्ती के अवसर पर उचित प्रबंध किये जाने का सुझाव दिया। सदस्य मनोज अरोरा ने भगोरिया के दौरान एम्बुलेंस की व्यवस्था, जेबकतरों एवं महिला सुरक्षा हेतु प्रबन्ध किये जाने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त भगोरिया के दौरान गुम होने वाले बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से माता-पिता द्वारा बच्चों के पास मोबाइल नं. एवं पते से सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अपील किये जाने का सुझाव दिया जिसे कलेक्टर द्वारा सहर्ष स्वीकार करते हुए जिलेवासियों से अपील की गयी छोटे बच्चों के पास माता-पिता के मोबाईल नं. एवं पते से सम्बन्धी जानकारी की पर्ची दी जाए जिससे गुम होने की स्थिति में बच्चों को ढुंढा जाना आसान हो सके। समिति के अन्य सदस्य संदेश सेठिया राणापुर निवासी द्वारा भगोरिया के दौरान व्यवस्थित मार्किंग किये जाने एवं पेयजल उपलब्धता हेतु सुझाव दिया। समिति के सदस्य नुरूद्दीन पिटोलवाला द्वारा रमजान के दौरान मस्जिद के आस-पास गश्त हेतु सुझाव दिया गया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र सिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ भास्कर गाचले, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर श्रीमती रीतिका पाटीदार, डिप्टी कलेक्टर हरिशंकर विश्वकर्मा, एसडीओपी झाबुआ श्रीमती रूपरेखा यादव, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।

बिहार में बदली स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर

नीतीश सरकार में कई नए मेडिकल कॉलेजों की हुई स्थापना

नेशनल डेस्क. नीतीश सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया गया है। काफी संख्या में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। राय के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की जा रही है। पटना के आईजीआईएमएस में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल खुल जाने से अब लोगों को अपनी आंखों के इलाज के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से इस अस्पताल का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही दरभंगा में एम्स के बन जाने से लोगों को सस्ता और बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 13

पहले की सरकारों ने बिहार की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए थे। पहले बिहार में नाम मात्र के मेडिकल कॉलेज थे जिसके कारण मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बिहार के छात्रों को बाहर जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार का शुरू से उद्देश्य रहा है कि इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई के लिए बिहार के छात्र-छात्राओं को बाहर नहीं जाना पड़े। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राय के सभी जिलों में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। बिहार में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुरू से मानना रहा है कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उनके जिले में ही उपलब्ध हो। स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने में जुटी नीतीश सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर गंभीर है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, छपरा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, झंझारपुर जल्द शुरू होने जा रहा है। इन दोनों मेडिकल कॉलेज के भवनों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं। नए मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से संबंधित जिलों के मरीजों को राहत मिलेगी और लोगों को चिकित्सा के लिए पटना का मुंह नहीं देखना पड़ेगा।

छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर

पहले बिहार में केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे। इसकी वजह से यहां के छात्र-छात्राओं को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए राय से बाहर जाना पड़ता था। धीरे-धीरे नीतीश सरकार में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 11 पहुंची और अब 9 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शुरू हो जाने से राय में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। नए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100-100 सीटें बढ़ जाएंगी। अभी बिहार में 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में 1490 नामांकन हो रहे हैं। राय में 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी संचालित हैं जहां पर एमबीबीएस की 1150 सीटों पर विद्यार्थियों का दाखिला होता है। इसके अलावे पटना डेंटल कॉलेज में 40 और रहुई डेंटल कॉलेज, नालंदा में 100 सीटें हैं। अभी पीएमसीएच पटना में 200, एनएमसीएच पटना में 150, एम्स पटना में 125, डीएमसीएच दरभंगा में 120, जेएलएनएमसीएच भागलपुर में 120, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में 120, एएनएमएमसीएच गया में 120, आइजीआइएमएस पटना में 120, जीएमसी बेतिया में 120, विम्स पावापुरी में 120, मधेपुरा में 100, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बिहटा में 100 और जीएमसी पूर्णिया में 100 सीटों पर एमबीबीएस कोर्स के लिए नामांकन होता है।

पटना के पीएमसीएच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जा रहा है। यहां 5400 से अधिक बेड के अस्पताल बनाने की प्रक्रिया जारी है। एनएमसीएच पटना एवं डीएमसीएच दरभंगा में भी बेडों की संख्या बढ़ाकर 2500 की जा रही है। ये सभी मेडिकल कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा शासित होंगे। नए मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के इलाज के लिए हर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी के अलावा न्यूनतम 500 बेडों की व्यवस्था की गई है। नीतीश सरकार की यह कोशिश है कि राय में ही लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज मिले। अगर किसी को बाहर इलाज कराने की इच्छा हो तो वे जा सकते हैं लेकिन राय में ही आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा बयान

2030 तक व्यापार दोगुना करेंगे मोदी-ट्रंप...

वाशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से अधिक तेल, गैस और लड़ाकू विमान खरीदने और टैरिफ में रियायत देने पर बातचीत का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, यह अभी तक दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर जारी गतिरोध को पूरी तरह समाप्त नहीं करता।

यह पेशकश व्हाइट हाउस में हुई दोनों नेताओं की बैठक के दौरान सामने आई, कुछ ही घंटे बाद जब ट्रंप ने भारत में अमेरिकी व्यवसायों के लिए व्यापारिक माहौल पर सवाल उठाए और सभी देशों पर रिसिप्रोकल टैरिफ (परस्पर शुल्क) लागू करने की योजना पेश की।

ट्रंप का भारत के टैरिफ पर कड़ा रुख

ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत के अनुचित और बहुत अधिक शुल्कों को कम करने की घोषणा की है, जो हमें भारतीय बाजार तक पहुंचने से रोकते हैं। यह वास्तव में एक बड़ी समस्या रही है।

दोनों नेताओं ने व्यापार संबंधी चिंताओं को हल करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री के अनुसार, यह समझौता अगले सात महीनों में हो सकता है। वहीं, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भी कोई समझौता संभव हो सकता है।

रक्षा और ऊर्जा सौदों पर बड़ा दांव

मोदी और ट्रंप की बैठक में कई बड़े मुद्दों पर सहमति बनी, जिसमें भारत की अमेरिकी रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने की योजना शामिल है। भारत अरबों डॉलर मूल्य के अमेरिकी रक्षा उपकरण, जिनमें लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, खरीदने की योजना बना रहा है। साथ ही, भारत अमेरिका को अपना नंबर एक तेल और गैस आपूर्तिकर्ता बना सकता है, ट्रंप ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।

मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच नाभिकीय ऊर्जा (न्यूक्लियर एनर्जी) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, हालांकि कानूनी बाधाएं अब भी बनी हुई हैं।

भारत को स्न-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने का प्रस्ताव

ट्रंप ने कहा, हम भारत को स्न-35 स्टील्थ फाइटर जेट उपलब्ध कराने का रास्ता भी साफ कर रहे हैं। हालांकि, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने स्पष्ट किया कि स्न-35 सौदा फिलहाल सिर्फ एक प्रस्ताव है और इस पर कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। व्हाइट हाउस से इस सौदे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

भारत-अमेरिका व्यापारिक तनाव बरकरार

हालांकि, ट्रंप और मोदी के बीच अच्छे संबंध हैं, फिर भी ट्रंप ने भारत के बहुत ऊंचे टैरिफ को लेकर दोबारा नाराजगी जताई।उन्होंने वादा किया कि अमेरिका भी भारत के शुल्कों के बराबर ही शुल्क लगाएगा। इससे पहले, ट्रंप की ओर से स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए आयात शुल्क का असर भारत जैसे धातु उत्पादक देशों पर काफी पड़ा था।

एक चीज जो मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सीखता हूं और जिसकी मैं सराहना करता हूं, वह यह है कि वे अपने देश के राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हैं। इसी तरह, मैं भी भारत के राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखता हूं, मोदी ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ बैठकर कहा।

भारत-अमेरिका का सुरक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी

दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। यह कदम चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है। इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ढ्ढ) और अन्य तकनीकों के संयुक्त उत्पादन पर भी चर्चा हुई। बैठक से पहले एक सूत्र ने कहा कि भारत द्वारा कुछ टैरिफ कम करने को ट्रंप के लिए उपहार के रूप में देखा जा सकता है, ताकि व्यापारिक तनाव कम हो सके। वहीं, एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ट्रंप का मानना है कि भारत को रक्षा और ऊर्जा निर्यात से अमेरिका के व्यापार घाटे में कमी आएगी।

अडानी मुद्दे पर मोदी का कड़ा जवाब

यह स्पष्ट नहीं हुआ कि भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़ा मामला बैठक में उठा या नहीं। अडानी को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा नवंबर में एक कथित रिश्वतखोरी योजना में आरोपित किया गया था। जब एक पत्रकार ने मोदी से पूछा कि क्या उन्होंने ट्रंप के साथ अडानी पर चर्चा की, तो मोदी ने नाराजगी जताते हुए जवाब दिया, देश आपस में मिलने के लिए इन विषयों पर चर्चा नहीं करते।

अमेरिका-भारत व्यापार: क्या चाहता है ट्रंप प्रशासन?

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंध आने वाले समय में मुकाबले की तरह होंगे। यह एक बॉक्सिंग मैच जैसा होगा, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के रिचर्ड रोसो ने कहा। भारत कुछ झटके सह सकता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होगी। अमेरिका का भारत के साथ 45.6 बिलियन का व्यापार घाटा है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, अमेरिका का औसत टैरिफ 2.2% है, जबकि भारत का औसत टैरिफ 12न है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अवैध आव्रजन पर अधिक सहयोग करे, क्योंकि भारत अमेरिका में प्रवासियों का एक बड़ा स्रोत है, खासकर तकनीकी क्षेत्र में।

मुंबई हमले के आरोपी का प्रत्यर्पण

राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के एक संदिग्ध के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। इस हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे।

मोदी-मस्क बैठक और व्यापारिक संभावनाएं

गुरुवार को मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात की। मस्क ट्रंप के प्रमुख समर्थकों में से एक हैं, और उनकी कंपनी स्टारलिंक दक्षिण एशियाई बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रही है।

चीन और रूस को लेकर भारत-अमेरिका की अलग राहें

ट्रंप प्रशासन भारत को चीन के खिलाफ रणनीतिक भागीदार के रूप में देखता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, और ट्रंप ने कहा कि वे भारत-चीन संघर्ष को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार हैं।

हालांकि, भारत अब भी रूस के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए हुए है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। जब से रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तब से भारत ने रूसी तेल का आयात जारी रखा है, जबकि पश्चिमी देश रूस से ऊर्जा आयात कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी ने इस पर कहा, दुनिया को यह धारणा थी कि भारत इस मामले में तटस्थ है, लेकिन यह सच नहीं है। भारत का पक्ष शांति का है।

ट्रंप और नेतन्याहू की चेतावनी से डरा हमास

इजरायली बंधकों को रिहा करने को हुआ तैयार

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी के बाद हमास बंधकों को रिहा करने को तैयार हो गया है। हाल ही में हमास ने इजरायली बंधकों की अगली रिहाई में देरी की धमकी दी थी। उसने इजरायल पर सहायता वितरण में शर्तों का सम्मान करने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि वह शनिवार को रिहा होने वाले तीन बंधकों को तब तक नहीं सौंपेगा, जब तक कि मुद्दा हल नहीं हो जाता।

हालांकि हमास ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह योजना के अनुसार तीन और इजराइली बंधकों को रिहा करेगा, जिससे गाजा पट्टी में संघर्ष-विराम को लेकर जारी विवाद के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। घोषणा के कुछ ही देर बाद, हमास के प्रवक्ता अब्दुल लतीफ अल-कानू ने फोन पर 'एसोसिएटेड प्रेस को पुष्टि की कि तीन बंधकों को शनिवार को रिहा कर दिया जाएगा।

इससे पहले, हमास ने एक बयान में कहा कि मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि वे सभी बाधाओं को दूर करने के लिए काम करेंगे, और संघर्ष-विराम समझौता लागू होगा। हमास की घोषणा के बाद इजराइल की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

हमास ने और इजराइली बंधकों की रिहाई टालने की धमकी दी थी, और इजराइल पर तंबुओं व शिविरों में रहने की अनुमति देने के दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। इसके अलावा, हमास ने इजराइल पर संघर्ष-विराम की अन्य शर्तों को तोड़ने का भी आरोप लगाया था। इजराइल ने बंधकों को रिहा न किए जाने की स्थिति में गाजा पट्टी में हमले फिर से शुरू करने की धमकी दी थी।

ट्रंप और मस्क के व्यापक कटौती के आदेश के बाद संघीय सरकार में बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू

नेशनल डेस्क: अरबपति एलन मस्क की टीम ने अमेरिकी संघीय कर्मचारियों की व्यापक छंटनी शुरू कर दी है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन सरकार के नागरिक कर्मचारियों की संख्या कम करने की दौड़ में है। द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, अब मस्क के सहयोगियों द्वारा संचालित कार्मिक प्रबंधन कार्यालय ने बुधवार को पुष्टि की है कि बल में कटौती शुरू हो गई है और एजेंसी पर इसका भारी असर पड़ रहा है।

बड़े पैमाने पर छंटनी और नियुक्ति पर रोक

व्हाइट हाउस सरकारी एजेंसियों में भारी बजट कटौती पर विचार कर रहा है जिसमें कई विभागों में 30न से 40न तक की कटौती की जाएगी। हालांकि, ट्रंप द्वारा पसंद की जाने वाली एजेंसियां, जैसे कि रक्षा विभाग और होमलैंड सुरक्षा, काफी हद तक इससे मुक्त हैं। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन की नियुक्ति पर रोक ने भर्ती को रोक दिया है, यहां तक कि वेटरन अफेयर्स विभाग (वीए) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी, जिससे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए आवश्यक नियुक्तियों में देरी हो रही है।

बर्खास्तगी में भ्रम और कुप्रबंधन

छंटनी के कारण पहले से ही व्यापक भ्रम की स्थिति है, संघीय कर्मचारियों को गलत बर्खास्तगी ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो और लघु व्यवसाय प्रशासन में कर्मचारियों को उनकी बर्खास्तगी के बारे में सूचित किया गया था लेकिन बाद में उन्हें परस्पर विरोधी संदेश प्राप्त हुए, जिसमें कहा गया था कि ईमेल गलती से भेजे गए थे और फिर उन्हें फिर से निकाल दिया गया। DOGE की नियुक्ति निगरानी ने भी नई नियुक्तियों के लिए राजनीतिक नियुक्तियों की स्वीकृति की आवश्यकता के कारण भर्ती को बाधित किया है जिससे एजेंसी का संचालन और धीमा हो गया है।

निर्मल सेठिया और चित्रा की अमर प्रेम कहानी: पत्नी की याद में बनाया 6500 करोड़ का म्यूजियम

नेशनल डेस्क. आज के समय में जहां रिश्ते बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती। वहीं 80 साल के कारोबारी निर्मल सेठिया और उनकी पत्नी चित्रा की प्रेम कहानी एक नई मिसाल पेश करती है। चित्रा के निधन के बाद भी निर्मल ने उनके प्यार को जिंदा रखा और उनकी याद में कई अद्भुत काम किए।

चित्रा के निधन को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन निर्मल ने उनकी यादों को सहेजने की ठानी। उन्होंने चित्रा के नाम पर यूके के कैम्ब्रिज में ऑटिम सेंटर और लंदन में चित्रा सेंटर फॉर रोबोटिक मास की शुरुआत की। इसके अलावा लंदन के

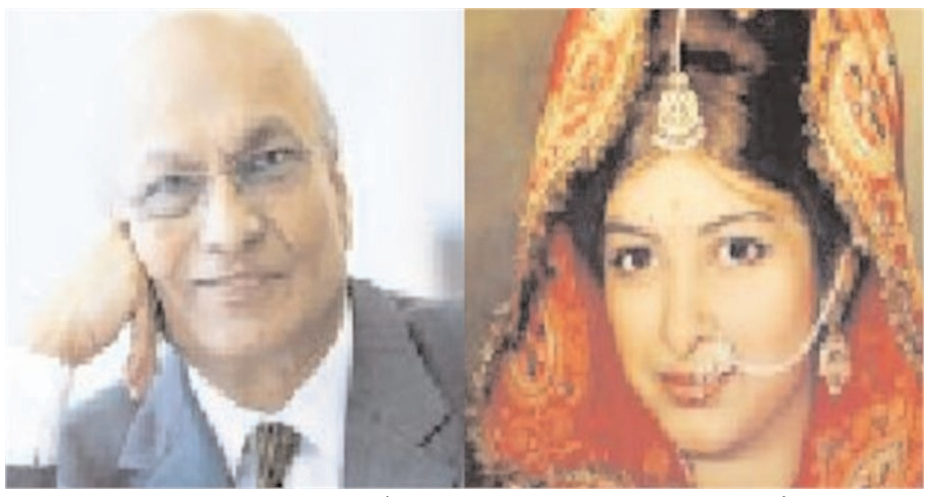

प्रसिद्ध विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में चित्रा सेंट्रल कास्ट कोर्ट गैलरी भी स्थापित की। निर्मल ने नई दिल्ली में एक मंदिर बनवाने के बाद कुरुक्षेत्र में भी अपनी पत्नी की याद में तिरुपति मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर उस स्थान पर बनाया गया, जहां महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने अंतिम सांस ली थी। यह कदम उनकी आस्था और चित्रा के प्रति उनके गहरे प्रेम को दर्शाता है।

3300 दुर्लभ चाय की केतलियों का अनोखा संग्रह

निर्मल सेठिया ने चित्रा कलेक्शन म्यूजियम की स्थापना यूके में की, जिसकी वैल्यूएशन लगभग 6500 करोड़ रुपए है। इस म्यूजियम में करीब 3300 दुर्लभ चाय की केतलियों और चाय से जुड़े बर्तनों का अनोखा संग्रह है। लंदन में 5 लाख वर्ग मीटर में बने इस म्यूजियम में 72 लाख ऐतिहासिक आइटम प्रदर्शित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस म्यूजियम के संरक्षक खुद किंग चार्ल्स हैं।

नोटों की सिक्योरिटी इंक के निर्माता

राजस्थान के सुजानगढ़ के मूल निवासी निर्मल सेठिया नोटों में इस्तेमाल होने वाली सिक्योरिटी इंक के निर्माता हैं। उनका विवाह जयपुर रिसायत में सेना में रहे जोरावर सिंह नाथावत की बेटी चित्रा से हुआ था। यह शादी 18 फरवरी 1969 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुई थी।

निर्मल और चित्रा की पहली मुलाकात राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर में हुई थी। एक आयोजन में निर्मल की मां ने चित्रा को देखा और उन्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। इसके बाद उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई और दोनों ने साथ मिलकर जीवन का सफर तय किया।

वर्तमान में कहां रहते हैं निर्मल सेठिया?

वर्तमान में निर्मल सेठिया दुबई और यूके में रहते हैं, लेकिन उनका दिल आज भी चित्रा की यादों में बसा है। उन्होंने अपने जीवन को उनकी यादों और नाम से जुड़े सामाजिक कार्यों में समर्पित कर दिया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569